कोटद्वार, मंगलवार
18 नवम्बर 2025
वर्षः 48
अंकः 184 पृष्ठः 4
मूल्यः 2.00

# जयन्त

निर्भीक – निष्पक्ष – जनसरोकार

www.dainikjayantnews.com
स्थापित 1979
संस्थापक : स्व. नगेन्द्र उनियाल

डाक पंजीयन पी.ए.ओ.07-2024-26 फोन: 9412081969 email: nagendra.uniyal@gmail.com

## संक्षिप्त समाचार

### लहबोली गांव में खेत में लगाई आग, मशरूम फसल जलकर राख

रुड़की। लंढौरा पुलिस ने दो दिन पहले एक घर से चोरी हुई नगदी और जेवर का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी को सोमवार को गिरफ्तार कर चोरी हुई नगदी और आभूषण भी बरामद भी कर लिए हैं। लंढौरा के मोहल्ला हरिजन बस्ती निवासी मनफूल 15 नवंबर को दिन में सपरिवार छत पर बैठा हुआ था। इसी दौरान घर के अंदर रखी आलमारी का ताला तोड़कर नकदी और सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए गए थे। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से पता चला कि घटना को अंजाम देने वाला आरोपी अंकित निवासी कपासा थाना नागल जिला सहारनपुर है। पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि घटना वाले दिन आरोपी लंढौरा में पड़ोस में किसी पास आया था। चौकी प्रभारी महिपाल सैनी ने बताया कि आरोपी के कब्जे से चोरी की गई नगदी और आभूषण बरामद कर लिए गए हैं। चौकी प्रभारी ने बताया कि 13 हजार रुपये और करीब साढ़े तीन लाख रुपये के आभूषण बरामद किए गए हैं। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है।

### आज बंद होंगे द्वितीय केदार मद्महेश्वर के कपाट

रुद्रप्रयाग : द्वितीय केदार भगवान मद्महेश्वर के कपाट शीतकाल के लिए आज बंद होंगे। पूजा-अर्चना और विधि विधान के साथ भगवान के मंदिर का गर्भ गृह बंद किया जाएगा। जबकि डोली ओंकारेश्वर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान करेगी। बदरी केदार मंदिर समिति ने कपाट बंद की सभी तैयारियां कर दी है। मंगलवार को सुबह पूजा अर्चना के बाद भगवान मद्महेश्वर के कपाट बंद होंगे। बीकेटीसी के अनुसार आज सुबह डोली मदमहेश्वर से चलकर रात्रि विश्राम के लिए गौंडार पहुंचेगी। जबकि 19 को भगवान की चल विग्रह डोली रांसी स्थित राकेश्वरी मंदिर पहुंचेगी। यहां रात्रि प्रवास के बाद डोली 20 नवम्बर को भगवान की डोली गिरिया पहुंचेगी जबकि 21 नवम्बर को डोली पंचकेदार गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचेगी जहां भगवान की छह महीने शीतकालीन पूजा-अर्चना की जाएगी। इस मौके पर ऊखीमठ में मद्महेश्वर मेला भी आयोजित किया जाएगा। (एजेंसी)

### हत्या के प्रयास में दो आरोपियों को सात–सात साल की सजा

रुद्रपुर। खटीमा की सूखी नहर में एक व्यक्ति को फेंककर जान से मारने की कोशिश के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश मंजू सिंह मुंडे की अदालत ने दो आरोपियों को सात–सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों आरोपियों पर दस–दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला 23 सितंबर 2023 का है। झनकइया थाना क्षेत्र निवासी शुभम ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि पड़ोस के प्रदीप सिंह राणा और अर्जुन सिंह उसके पिता राजेंद्र प्रसाद को घर से मोटरसाइकिल पर लेकर गए और रास्ते में जान से मारने की नीयत से उन्हें सूखी नहर में फेंक दिया। पुलिस के जवानों ने घायल पिता को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां पता चला कि उनकी रीढ़ और पैर की हड्डी टूट गई है। आरोपियों ने मुकदमा दर्ज कराने पर परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा 307 सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता सौरभ ओझा ने 11 गवाह पेश किए। अदालत ने सभी आरोपों में दोनों को दोषी पाया। अदालत ने दोनों को सात–सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। बाद में दोनों को उपजिला कारागार हल्द्वानी भेज दिया गया।

### एसआईआर कराकर महागठबंधन के वोट काटे गए, हमें हराया गया : पप्पू यादव

पटना ,बिहार चुनाव के नतीजों में महागठबंधन को बहुत कम सीट मिली। गठबंधन में शामिल दलों के बीच हार की समीक्षा की जा रही है। इस बीच कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने महागठबंधन की हार का जिम्मेदार एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) को बताया। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने कहा, बिहार चुनाव में हम हारे नहीं, बल्कि हराए गए। 128 सीटों पर एनडीए गठबंधन उतनी मार्जिन से जीता, जितना एसआईआर करके महागठबंधन के वोट को काटा गया और बाद में करीब 21 लाख के करीब भाजपा के वोट को जोड़ा गया।

# बिहार में 20 नवंबर को गांधी मैदान में होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण

## पीएम मोदी भी होंगे शामिल

पटना ,बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की ऐतिहासिक जीत के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। एनडीए की नई सरकार का भव्य शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। एनडीए ने 243 सदस्यीय विधानसभा में 202 सीटों का प्रचंड बहुमत हासिल किया है। इस जीत में भाजपा को 89, जेडीयू को 85, एलजेएपी (रामविलास) को 19 और अन्य सहयोगी दलों को 9 सीटें मिली हैं।

**कौन होगा अगला मुख्यमंत्री?**

इस्तीफे के बाद, पहले जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक होगी, जिसमें नीतीश कुमार को नेता चुने जाने की उम्मीद है। इसके बाद बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होगी और अंत में एनडीए विधानमंडल दल की एक संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी। इस संयुक्त बैठक में गठबंधन का नेता चुने जाने की उम्मीद है, जिसके बाद एनडीए प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश करेगा।

हालांकि, इस बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है कि 20 नवंबर को नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे या एनडीए सरकार के तौर पर कोई और नेता यह जिम्मेदारी संभालेगा।

**गांधी मैदान में भव्य तैयारी**

शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पटना के गांधी मैदान को 20 नवंबर तक आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है, ताकि समारोह सुचारू रूप से संपन्न हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा, इस समारोह में कई केंद्रीय मंत्रियों, गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और एनडीए के अन्य वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है।

### दुष्कर्म के दोषी युवक को 20 साल की सजा

हरिद्वार। आठ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अपर जिला जज एफटीएस कोर्ट न्यायाधीश रमेश सिंह ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी युवक को 20 वर्ष कठोर कारावास और दो लाख 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा भी सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 22 अप्रैल 2023 को मंगलौर क्षेत्र में एक आठ वर्षीय बच्ची अपने भाई और मामू के साथ मेला देखने घर से गई थी।

काफी देर तक घर नहीं लौटने पर शिकायतकर्ता पिता ने बच्ची के मामू को फोन कर बच्ची के बारे में पूछा। जिस पर मामू ने कहा कि मैंने आपके दोनों बच्चों को घर भिजवा दिया था। उसी रात करीब 11 बजे पीड़ित बच्ची जंगल में बदहवाश हालत में परिजनों को मिली थी। पीड़ित बच्ची ने अपने परिजनों को बताया कि आरोपी अयाज उसे मेले से उठाकर जंगल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही, किसी को बताने पर आरोपी जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़ित बच्ची के शिकायतकर्ता परिजनों ने आरोपी अय्याज पुत्र जव्वाद, निवासी मोहल्ला कट-हड़ा मंगलौर के विरुद्ध संबंधित धाराओं में केस दर्ज कराया था।

# व्यापारिक तनाव के बीच अमेरिका से एलपीजी खरीदेगा भारत

नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत हो गया है। सोमवार को भारत ने बताया है कि वह अमेरिका से पहली बार एलीपीजी की खरीद करने जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पर रूस से इनर्जी खरीद कम करने और अमेरिका बढ़ाने को लेकर दबाव बना रहे थे। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 17 नवंबर को इसकी घोषणा करते हुए बताया कि सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों (इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल) ने अमेरिका की खाड़ी तट से 2026 कैलेंडर वर्ष के लिए करीब 22 लाख टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) एलपीजी आयात का एक साल के अनुबंध को अंतिम रूप दे दिया है। यह भारत के कुल वार्षिक एलपीजी आयात का लगभग 10 प्रतिशत है।

**एलपीजी बाजार अब अमेरिका के लिए खुला**

पेट्रोलियम मंत्री पुरी ने इसे ह्लऐतिहासिक उपलब्धि" करार देते हुए कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ता एलपीजी बाजार अब अमेरिका के लिए खुल गया है। जुलाई 2025 में तीनों पीएसयू कंपनियों के अधिकारियों की अमेरिका यात्रा और वहां प्रमुख अमेरिकी उत्पादकों के साथ हुई बातचीत के बाद यह सौदा पूरा हुआ है। यह सौदा ऐसे समय में हुआ है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव चरम पर है।

अमेरिका लंबे समय से भारत पर दबाव बना रहा है कि वह अपनी पेट्रोलियम जरूरतों के लिए रूसी तेल एवं उत्पादों की खरीद कम करे और इसके बदले अमेरिकी कंपनियों से ज्यादा ऋूड ऑयल, एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम उत्पाद खरीदे। ट्रंप प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने कई मौकों पर भारत को रूस से तेल खरीदने पर अप्रत्यक्ष रूप से चेतावनी दी है। इससे दोनों देशों के बीच संबंधों पर उल्ट असर भी पड़ा है।

**रूसी ऋूड की खरीद में उल्लेखनीय कमी**

वैसे आधिकारिक तौर पर भारत ने तो यह कहा कि वह अपनी ऊर्जा जरूरत के हिसाब से जहां से जरूरत होगी वहां से तेल खरीदेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि भारतीय रिफाइनरियों ने रूसी ऋूड की खरीद में उल्लेखनीय कमी शुरू कर दी है। तकरीबन दो वर्षों तक रूस भारत के शीर्ष तीन तेल आपूर्तिकर्ता देशों में शामिल रहा लेकिन अब फिर से खाड़ी के देश (सउदी अरब, ईराक, यूएई आदि) शीर्ष पर लौट आए हैं।

# पिछले तीन साल में बनें स्थाई निवास प्रमाण पत्रों की होगी जांच : धामी

## मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की

**जयन्त प्रतिनिधि। देहरादून :** मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के जिलाधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने बैठक में राज्य के विकास कार्यों की प्रगति, जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण और प्रशासनिक सुधारों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को पिछले तीन साल में बने स्थाई निवासी प्रमाण पत्रों की जांच के निर्देश देते हुए गलत तरीके से बने प्रमाण पत्र में संलिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए जिला स्तर पर नियमित सत्यापन और निरीक्षण अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने सीमा क्षेत्रों में विशेष निगरानी बनाए रखने और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही, शहरों और संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरों की पूरी व्यवस्था और उनकी रियल-टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के विजन पर जोर दिया और 'एक जिला, एक मेला' अभियान के महत्व को रेखांकित करते हुए स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने वाले मेलों के पर्यावरण-सम्मत और भव्य आयोजन की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ह्लएक जिला, एक मेलाह्व अभियान के अंतर्गत चयनित मेलों को राजकीय मेला के रूप में घोषित किया जाएगा। जिन मेलों को यह मान्यता प्राप्त होगी, उन्हें विशेष संरक्षण, वित्तीय सहायता और प्रचार-प्रसार का लाभ मिलेगा। इन मेलों के आयोजक वही रहेंगे। राज्य सरकार केवल सहायता और आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी। इस अभियान का उद्देश्य केवल स्थानीय संस्कृति, कला और शिल्प को बढ़ावा देना ही नहीं, बल्कि जनता के लिए मनोरंजन और सामुदायिक सहभागिता के अवसर भी प्रदान करना है। राजकीय मेला घोषित किए जाने से मेलों का स्वरूप और आकर्षण और बढ़ जाएगा तथा यह राज्य के सांस्कृतिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

### सीमा से लगे गांवों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करें

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीमा से लगे गांवों को वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्देश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक सीमांत गांव को किस रूप में आकर्षण का केंद्र बनाया जाएगा। उन्होंने शीतकालीन चार धाम यात्रा और बारहमासी पर्यटन की तैयारियों को तेज करने के निर्देश दिए। इसके अंतर्गत, विशेषकर उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में होटलों, होमस्टे संचालकों और अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय स्थापित करना और यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएँ उपलब्ध कराना शामिल है।

### ब्लॉक में एक गांव को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुने

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड को देश और दुनिया के लिए आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने के दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि योग, आयुर्वेद और ध्यान के केंद्रों को जिलों और ब्लॉकों तक विस्तारित किया जाए। इसके लिए प्रत्येक ब्लॉक में एक गांव को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना जा सकता है, जिसे ह्लआध्यात्मिक गाँवह्व के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पहल के तहत गाँव में योग प्रशिक्षण केंद्र, आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सुविधा, ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा स्थानीय स्तर पर आध्यात्मिक शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इससे न केवल स्थानीय लोगों का स्वास्थ्य और मानसिक शांति बढ़ेगी, बल्कि राज्य को पर्यटन और स्वास्थ्य से जुड़ी नई पहचान भी मिलेगी।

### बहन रोहिणी के अपमान पर भड़के तेज प्रताप

पटना ,राजद सुप्रीमो सीएम लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बहन रोहिणी आचार्य से जुड़े विवाद पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने कहा कि मेरी बहन का अपमान किसी भी हाल में असहनीय है। सुन लो जयचंदों परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। तेज प्रताप यादव ने राजद प्रमुख लालू यादव से आग्रह करते हुए कहा कि आपका केवल एक इशारा और बिहार की जनता इन जयचंदों को जमीन में खुद गाड़ देगी। बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की करारी हार के बाद लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भाई तेजस्वी यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए। रोहिणी ने बताया है कि उन्हें पीटने के लिए चप्पल तक उठाई गई। रोहिणी के आरोप पर भाई तेज प्रताप ने सोशल मीडिया के माध्यम से जवाब दिया है। जनता दल जनता (जेजेडी) प्रमुख तेज प्रताप ने अपने पार्टी के इंस्टाग्राम हैंडल पर लिखा,कल की घटना ने दिल को भीतर तक झकझोर दिया है।

# दिल्ली ब्लास्ट केस : अदालत ने आमिर राशिद अली को 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेजा

नई दिल्ली ,दिल्ली की अदालत ने कार ब्लास्ट मामले में ड्राइवर उमर मोहम्मद उर्फ उमर उर नबी के सहयोगी आमिर राशिद अली को 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेजा है। आमिर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने रविवार को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। एनआईए ने सोमवार को दिल्ली की अदालत में आमिर राशिद अली को पेश किया और उसकी कस्टडी मांगी। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने एनआईए को 10 दिन की कस्टडी सौंपी। आमिर राशिद अली से पूछताछ के दौरान एनआईए को कई अहम कड़ियों को जोड़ने में मदद मिल सकती है। आमिर राशिद अली जम्मू–कश्मीर के पंपोर के संबूरा का रहने वाला है। सूत्रों के अनुसार, एनआईए की जांच से पता चला है कि आमिर ने उमर उन नबी के साथ मिलकर आतंकी हमला करने की साजिश रची थी। एक बयान में कहा गया, आमिर कार की खरीद में मदद करने के लिए दिल्ली आया था, जिसमें विस्फोट हुआ था। इस आतंकी हमले की जांच के सिलसिले में एनआईए को आमिर की गिरफ्तारी के रूप में सफलता मिली। एनआईए ने दिल्ली पुलिस से मामला अपने हाथ में लेने के बाद व्यापक तलाशी अभियान चलाया था।

दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार ब्लास्ट में कम से कम 12 लोग मारे गए थे, जबकि कई लोग बुरी तरह घायल हुए। यह ब्लास्ट फरीदाबाद में आतंकी मॉड्यूल के खुलासे के कुछ घंटे बाद हुआ था, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल और शाहीन समेत सात लोगों को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कार ब्लास्ट में शामिल उमर का भी फरीदाबाद के आतंकी मॉड्यूल से कनेक्शन सामने आया था।

# 5 करोड़ रुपए मूल्य के 30,000 चीनी पटाखे जब्त, एक गिरफ्तार : डीआरआई

मुंबई , राजस्व खुफिया विभाग (डीआरआई) ने चीन से आने वाले पटाखों और आतिशबाजी की अवैध तस्करी का एक और बड़ा मामला पकड़ा है। सोमवार को इसकी जानकारी दी गई। टीम ने इस तस्करी को रोक दिया। अब तक का यह एक और सफल अभियान है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि पटाखों की तस्करी रोकने के लिए चल रहे फायर ट्रेल अभियान चलाया गया, जिसमें डीआरआई ने मुंद्रा बंदरगाह पर बड़ा काम किया। टीम ने 5 करोड़ रुपए की कीमत के 30,000 अवैध पटाखे पकड़े और एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। इस अभियान के दौरान, डीआरआई अधिकारियों ने मुंद्रा बंदरगाह पर चीन से आए एक 40 फुट लंबे कंटेनर को पकड़ा, जिस पर पानी का गिलास और फूलदान होने का दावा किया गया था। लेकिन जांच में पानी के गिलास के एक सेट के पीछे 30,000 छिपे हुए पटाखे/आतिशबाजी के टुकड़े मिले। डीआरआई ने कहा कि आयातक के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं थे और उसने स्वीकार किया कि माल की तस्करी आर्थिक लाभ के लिए की गई थी। इससे पहले, अक्टूबर महीने में, डीआरआई ने मुंबई और तूतीकोरिन में चीनी पटाखों के अवैध आयात के प्रयासों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया था। इसमें अकेले अक्टूबर महीने में, डीआरआई मुंबई क्षेत्रीय इकाई (एमजेडयू) ने लगभग 16 करोड़ रुपये मूल्य के अवैध रूप से आयातित पटाखे जब्त किए।मंत्रालय के अनुसार, विदेश व्यापार नीति के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के तहत पटाखों का आयात प्रतिबंधित है और इसके लिए विस्फोटक नियम, 2008 के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) और पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) दोनों से वैध लाइसेंस की आवश्यकता होती है। डीआरआई ने कहा, ऐसे खतरनाक सामान की गैरकानूनी तस्करी से लोगों की जान को खतरा है। देश की सुरक्षा, बंदरगाह, जहाज और पूरे व्यापार को बड़ा नुकसान हो सकता है। हम तस्करों के बड़े–बड़े नेटवर्क को ढूंढेंगे और खत्म करेंगे। खतरनाक तस्करी से लोगों को बचाएंगे।

### 4 हस्तियों के घरों पर बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने शुरू की जांच

चेन्नई ,तमिलनाडु से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। रविवार देर रात मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन सहित अभिनेता अजित कुमार, अरविंद स्वामी और खुशबू के घरों को बम धमाके की धमकी दी गई। मामले की जानकारी मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया और पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी।

सूत्रों के मुताबिक, इन चारों के आवास पर बम होने की धमकी से जुड़ा ईमेल पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कार्यालय को भेजा गया था। इसके बाद पुलिस टीमों ने सभी चार घरों पर पहुंचकर सुरक्षा जांच और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। अधिकारी ईमेल की सत्यता और इसके स्रोत की भी पड़ताल कर रहे हैं।

# नहीं सुधर रहे प्रदूषण के हालात, कई इलाकों में एक्यूआई 400 पार पहुंचा

नई दिल्ली ,दिल्ली–एनसीआर में सोमवार को हवा की गुणवत्ता बहुत खराब से गंभीर स्तर तक बनी रही। राजधानी के ऊपर धुंध की मोटी चादर छाई रही। सुबह 6 बजे दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 रहा। छह जगहों पर यह 400 से ऊपर दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। अलीपुर में सूचकांक 386, आनंद विहार 384, अशोक विहार 392, चांदनी चौक 383, आईटीओ 394, लोधी रोड 337, मुंडका 396, नेहरू नगर 389 और सिरीफोर्ट में 368 दर्ज हुआ। वहीं बवाना 427, डीटीयू 403, जहांगीरपुरी 407, नरेला 406, रोहिणी 404 और वजीरपुर में एक्यूआई 401 तक पहुंच गया, जो सभी गंभीर श्रेणी में आते हैं।

वहीं, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के प्रदूषण में भी सुधार नहीं हो रहा है। यहां सोमवार को प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में है। नोएडा के सेक्टर 62 का एक्यूआई 319, सेक्टर 116 का 361, सेक्टर 1 का 361, सेक्टर 125 का 383 दर्ज किया गया। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 3 का एक्यूआई 356, नॉलेज पार्क 5 का 416 दर्ज किया गया। लगातार आबोहवा खराब होने से सांस की समस्या से परेशान मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसी बीच, राष्ट्रीय राजधानी और आस–पास के इलाकों में बढ़ते प्रदूषण पर दायर जनहित याचिका की सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर शुरू होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी जानकारी के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्तियों के. विनोद चंद्रन व एन.वी. अंजारिया की पीठ 17 नवंबर को इस मामले पर आगे सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई में अदालत ने चिंता जताई थी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू होने के बावजूद प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार से पराली जलाने पर रोक के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा था। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि दिल्ली–एनसीआर के कई हिस्सों में सूचकांक 450 के पार पहुंच गया है।

# महिलाओं को 10 हजार देने के लिए वर्ल्ड बैंक का फंड हुआ इस्तेमाल

## पीके की पार्टी ने एनडीए पर लगाए गंभीर आरोप

पटना , जन सुराज के प्रवक्ता और वरिष्ठ पार्टी रणनीतिकार पवन वर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार पर एक सनसनीखेज आरोप लगाया है। वर्मा ने दावा किया है कि बिहार विधानसभा चुनावों में चुनावी लाभ लेने के लिए विश्व बैंक द्वारा समर्थित एक प्रोजेक्ट के लिए आवंटित धनराशि का दुरुपयोग किया गया। वर्मा के अनुसार, इस पैसे को 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिला मतदाताओं में बांटा गया। उन्होंने बताया कि बिहार में 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में 10,000–10,000 रुपए जमा किए गए, लेकिन उन्होंने इस धन के स्रोत और इसके ट्रांसफर के समय पर गंभीर संदेह जताया।

**आचार संहिता से एक घंटा पहले बांटे 14,000 करोड़**

पवन वर्मा ने पार्टी को मिली जानकारी का हवाला देते हुए बिहार की वित्तीय स्थिति पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा,बिहार में सरकारी कर्ज इस समय 4,06,000 करोड़ रुपए है। प्रतिदिन का ब्याज 63 करोड़ रुपए है। खजाना खाली है। इसके बाद उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा,पार्टी ने सुना है हालांकि यह गलत हो सकता है कि 10,000 रुपए का ट्रांसफर उन 21,000 करोड़ रुपये से दिया गया था, जो विश्व बैंक से किसी अन्य प्रोजेक्ट के लिए आया था। वर्मा ने यह भी दावा किया कि,चुनाव आचार संहिता लागू होने से एक घंटा पहले, 14,000 करोड़ रुपए निकालकर राज्य की 1.25 करोड़ महिलाओं में बांट दिए गए।

**'अगर सच है, तो यह कितना नैतिक?**

हालांकि, पवन वर्मा ने ज़ोर देकर कहा कि वह इस जानकारी को स्थापित तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा,जैसा कि मैंने कहा, यह हमारी जानकारी है। अगर यह गलत है, तो मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन अगर यह सच है, तो सवाल उठता है कि यह कितना नैतिक है। जन सुराज नेता ने तर्क दिया कि अचानक हुए इस वित्तीय वितरण ने मतदाताओं को अनिवार्य रूप से प्रभावित किया और उनकी नई पार्टी के संदेश को फीका कर दिया।

### 'कसम खाता हूँ, फिलिस्तीन देश नहीं बनने दूंगा नेतन्याहू का ऐलान

न्यूयॉर्क/यरूशलेम ,गाजा में युद्धविराम लागू होने के बाद अब अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिलिस्तीन राष्ट्र को लेकर एक अहम प्रस्ताव पेश करने जा रहा है। हालांकि, इस प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खा ली है कि वह किसी भी कीमत पर फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना का समर्थन नहीं करने वाले हैं।

नेतन्याहू लंबे समय से यह कहते रहे हैं कि एक अलग फिलिस्तीनी राष्ट्र बनाने से आतंकी संगठन हमास को ही लाभ होगा। उन्होंने आशंका जताई है कि इससे इजरायल की सीमाओं पर अंततः हमास द्वारा संचालित एक और भी बड़ा राष्ट्र बन जाएगा।

# उत्तराखंड में अब जमीन और फ्लैट खरीदना हुआ महंगा

## शासन ने रजिस्ट्री की फीस 50 हजार रुपये तक बढ़ाई

देहरादूनः प्रदेश में सोमवार से भूमि और परिसंपत्तियों की रजिस्ट्री महंगी हो गई है। शासन ने रजिस्ट्रेशन शुल्क 25 हजार रुपये से बढ़ाकर अधिकतम 50 हजार रुपये कर दिया है। रजिस्ट्रेशन शुल्क में यह वृद्धि 10 वर्ष बाद की गई है।

बढ़े हुए शुल्क का उपयोग प्रदेशभर में रजिस्ट्री कार्यालयों की दशा सुधारने और उन्हें आधुनिक बनाने में किया जा सकेगा। प्रदेश में भूमि एवं परिसंपत्ति खरीदने और उसकी रजिस्ट्री कराने पर जेब अधिक ढीली करनी पड़ेगी। सरकार गत माह सर्किल रेट बढ़ा चुकी है। अब भूमि या परिसंपत्ति की रजिस्ट्री पर लिए जाने वाले शुल्क में वृद्धि की गई है। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी किए। सरकार ने इससे पहले 14 सितंबर, 2015 में रजिस्ट्रेशन शुल्क 25 हजार रुपये नियत किया था। 10 वर्ष बाद इस शुल्क में वृद्धि की गई है। यद्यपि, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की भांति रजिस्ट्रेशन शुल्क एक प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया था।

सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इस प्रस्ताव से अधिक मूल्य यानी करोड़ों रुपये की परिसंपत्तियों पर रजिस्ट्रेशन शुल्क बढ़ने की स्थिति बनती। ऐसे में इस शुल्क को बढ़ाकर 50 हजार रुपये अधिकतम रखा गया है। इससे काफी अधिक कीमत की परिसंपत्तियों पर रजिस्ट्रेशन शुल्क अधिकतम 50 हजार रुपये रहेगा।

## सम्पादकीय

# आंकड़ों पर सवाल

उत्तराखंड में मानसून के बाद क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को लेकर राज्य सरकार ने युद्ध स्तर पर काम किया है और दावा किया जा रहा है कि 90% से अधिक सड़कों को आवागमन के लायक बना दिया गया है, हालांकि एक पक्ष अभी कहता है कि जो आंकड़े सरकार पेश कर रही है वह हकीकत से कहीं दूर है और अधिकांश सड़कों में लीपा पोती कर उन्हें बनाया गया है। इस बार मानसून ने उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में सड़कों को बुरी तरह से प्रभावित किया। खास तौर से पहाड़ों में तो कई कई किलोमीटर की सड़क पूरी तरह से नष्ट हो गई जहां यातायात आवागमन को सुचारु करने के लिए सरकार को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। आज भी ऐसे कई स्थान है जहां वैकल्पिक व्यवस्था कर यातायात चलाया जा रहा है। कुछ ऐसे ही हालात राजधानी देहरादून में भी है जहां बरसात में क्षतिग्रस्त हुआ प्रेम नगर का पुल अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ है। अब सरकार के यह आंकड़े किस आधार पर पेश किए गए हैं यह तो सरकार ही जाने लेकिन विपक्ष के इस कथन में कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई है कि आंकड़े हकीकत से मेल नहीं खाते। इस मानसून की भीषण बारिश ने उत्तराखंड में अपने पीछे कई दर्द देने वाले निशान छोड़े हैं। मानसून के बाद कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण सड़के बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। चार धाम यात्रा से पूर्व इन सड़कों को आवागमन की योग्य बनाया गया था, जिनकी अब हालत मानसून के बाद खराब हुई। प्रदेश सरकार द्वारा पहाड़ों में सड़कों की दशा सुधारने एवं निर्माण को लेकर अच्छा खासा बजट खर्च किया जाता है लेकिन कहीं घटिया गुणवत्ता के कारण सड़क अधिक नहीं चलती तो कहीं प्राकृतिक आपदा की आड़ में सड़कों की निम्न गुणवत्ता और टिकाऊपन बह जाता है। जरूरी है कि उत्तराखंड में पहाड़ों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सड़कों के निर्माण के लिए तैयारी की जानी चाहिए। प्राकृतिक आपदा को छोड़ दें तो कई स्थानों पर तो ठेकेदारों ने अपनी नाकामियों का ठीकरा भी प्रकृति पर फोड़ दिया। पहाड़ी क्षेत्र में सड़कों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है ताकि न केवल स्थानीय लोगों को आवागमन की सुविधा हो बल्कि दुर्घटना से भी बचा जा सके। इसके अलावा पहाड़ों की सड़क स्थानीय लोगों की आजीविका को चलाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और यदि सड़के ही क्षतिग्रस्त रहेंगी तो व्यावसायिक एवं सामाजिक अव्यवस्थाएं भी पैदा होगी। पिछली बरसात में भी उत्तराखंड के पहाड़ों में सड़कों की बुरी दशा हुई है और कई सड़के तो ऐसी है जिन्हें दुरुस्त और पुरानी अवस्था में लाने के लिए लंबा समय लगने वाला है। सड़कों के निर्माण को लेकर कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाओं को भी नजरअंदाज किया गया है जिसका मुख्य उदाहरण ऑल वेदर रोड है जिसे कई स्थानों पर ऐसे पहाड़ों को काटकर निकाला जा रहा है, जो कभी भी दरक सकते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में पर्यटन की संभावनाएं तलाशी जा रहीं हैं, लेकिन यदि परिवहन व्यवस्था ही जर्जर हालत में होगी तो फिर एक विकसित पर्यटन की कल्पना कैसे की जा सकती है? पहाड़ों में मैदानों जैसी व्यवस्थाओं के तहत सड़कों का निर्माण ना तो किया जा सकता है और ना ही यह सफल साबित होगी। इसके लिए उन्नत तकनीक की जरूरत है जो पहाड़ों में ही कारगर साबित हो। भारी बारिश से नष्ट हुई सड़कों की दशा ठीक करने के लक्ष्य पर सरकार को काम करना चाहिए। कई स्थानों पर सड़कों का पुनर्निर्माण किया गया है और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में प्रदेश भर में सड़कों की स्थिति सुलभ आवागमन के लायक देखने को मिलेंगी।

# व्यवसाय से संबंधित सम्पूर्ण व्यवस्था और श्रम कल्याण के लिए वेतन संहिता

**ओम प्रकाश गुप्ता**

आज की वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में, जहाँ न्यायसंगत वेतन, सम्मानजनक कार्य और श्रमिक संरक्षण टिकाऊ विकास के मूल तत्व हैं, वेतन संहिता, 2019 भारत के लिए प्रवर्तन से सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को इंगित करती है। वियतनाम जैसे अनेक? विकासशील देशों के उदाहरण दर्शाते हैं कि समयबद्ध और सुविचारित श्रम सुधार किस प्रकार सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करते हुए आर्थिक वृद्धि को गति दे सकते हैं। वियतनाम में न्यूनतम वेतन सुधार और श्रमिकों की सुरक्षा के संवर्धित उपायों सहित श्रम कानूनों के किए गए बदलावों की बदौलत विदेशी निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और औपचारिक रोजगार में निरंतर वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने लगातार इस बात पर बल दिया है कि न्यायसंगत वेतन प्रथाओं को सुनिश्चित करना विशेष रूप से गरीबी उन्मूलन, सम्मानजनक कार्य और समावेशी आर्थिक विकास से संबंधित लक्ष्यों सहित सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति के लिए आवश्यक है । साथ ही, दुनिया भर के व्यवसायों ने अत्यधिक नियामक बोझ, जटिल अनुपालन संरचनाओं, और दंडात्मक प्रवर्तन के बारे में चिंता भी व्यक्त की है, जो तेजी से बदलते वैश्विक बाजार में उनकी प्रगति और प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न करते हैं।

दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने और वैश्विक श्रम बाजार में अहम प्रतिभागी होने नाते भारत इन चुनौतियों से अछूता नहीं है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही क्षेत्रों में कार्यरत विशाल कार्यबल (53.53 करोड़) के साथ (आर्थिक समीक्षा, 2021–22), देश ने लंबे समय तक श्रमिकों के लिए वेतन में बराबरी सुनिश्चित करने और नियोक्ता ओं के लिए अनुपालन के ढाँचे को आसान बनाने की दोहरी चुनौती का सामना किया है।

वेतन से जुड़े अनेक कानूनों (वेतन भुगतान अधिनियम, 1936; न्यू।नतम वेतन अधिनियम, 1948; बोनस भुगतान अधिनियम, 1965; और समान पारिश्रमिक अधिनियम,1976) और उनके ओवरलैपिंग प्रावधानों तथा उन्हें लागू करने में आने वाली मुश्किलों की वजह से अक्सर नियोक्तागओं के लिए भ्रम, दोहराव और अनुपालन की चुनौतियाँ उत्पकन्नस होती थीं। इन कमियों ने आर्थिक उत्पादकता और श्रमिकों के कल्याण दोनों में बाधा उत्पतन्नी की। वेतन संहिता, 2019 इन चारों मौजूदा कानूनों को एक ही सुव्यवस्थित ढाँचे में समेकित कर इन समस्याओं को हल करती है। यह सरलीकरण वेतन मानकों की एक जैसी परिभाषाएँ और लगातार अनुपालन सुनिश्चित करता है, जिससे गैर–ज़रूरी ओवरलैप खत्म होते हैं और नियोक्ताहओं के लिए अनुपालन आसान हो जाता है, साथ ही श्रमिकों को समय पर और न्यातयसंगत वेतन की गारंटी मिलती है। यह संहिता प्रशासनिक जटिलता को कम करके, पारदर्शिता, दक्षता और नियोक्तान–कर्मचारी संबंधों में बेहतरी को बढ़ावा देने के प्रति लक्षित है। इस तरह, वेतन संहिता, भारत का अपनी श्रम नीतियों को वैश्विक सवोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाने का प्रयास है। जो यह सुनिश्चित करती है कि श्रमिकों की सुरक्षा और व्यावसायिक दक्षता दोनों का एक–दूसरे को मज़बूत करते हुए साथ–साथ आगे बढ़े।

वेतन की एकसमान परिभाषाः वेतन संहिता, 2019 के तहत लाया गया एक मुख्य सुधार वेतन की एक समान और पूरी परिभाषा को अपनाया जाना है, जो पहले के विभाजित दृष्टिकोण की जगह लेता है, जिसमें हर श्रम कानून की अपनी अलग परिभाषा थी। इस असंगतता के कारण नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों के लिए अक्सर भ्रम, मुकदमेबाजी और अनुपालन संबंधी चुनौतियाँ उत्पन्न होती थीं, क्योंकि एक ही शब्द वेतन विभिन्न उद्देश्यों के लिए अलग–अलग अर्थ रखता था। परिभाषा को मानकीकृत करके, वेतन संहिता वेतन गणना में ज़्यादा पारदर्शिता और प्रशासनिक सरलता लाएगी। अब यह एकसमान परिभाषा स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करती है कि वेतन में क्या–क्या शामिल होगा, जिसमें मूल वेतन, महंगाई भत्ता और प्रतिधारण भत्ता शामिल हैं, जबकि बोनस, गृह किराया भत्ता और ओवरटाइम भुगतान जैसे खास घटकों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। नियोक्ता के लिए, यह नियामक स्पष्टता और अनुपालन में आसानी देती है, जिससे सभी क्षेत्रों में ज़्यादा पारदर्शी और न्यायसंगत वेतन संरचना को बढ़ावा मिलता है।

निरीक्षक झ सुविधा प्रदाता के रूप में : वेतन संहिता, 2019 की एक बड़ा बदलाव लाने वाली विशेषता निरीक्षकों की भूमिका को नए सिरे से परिभाषित करना है। पहले के कानूनों के तहत, निरीक्षक मुख्य रूप से लागू करने वाले या प्रवर्तक के तौर पर काम करते थे, जिससे अक्सर नियोक्ता ओं के साथ उनके रिश्ते टकरावपूर्ण हो जाते थे। दुनिया भर में, नियामक प्रणालियों में नियमों के सख्त प्रवर्तन के स्था न पर उनमें सुविधा देने का बदलाव आया है, जहाँ नियामक अब नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने में भागीदार के तौर पर काम करते हैं। इस वैश्विक प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, वेतन संहिता, 2019 निरीक्षक की भूमिका को निरीक्षक–सह–सुविधा प्रदाता के रूप में पुनर्परिभाषित करती है, जिसका आशय है कि निरीक्षकों को अब सिर्फ लागू करने वाले के तौर पर नहीं, बल्कि सुविधा प्रदाता के तौर पर देखा जाता है; जो नियोक्तोओं के लिए मार्गदर्शक, शिक्षक और सहयोगी के रूप में काम करते हैं। अब उनकी भूमिका में व्यवसायों को नियमों को समझने और उनका पालन करने में मदद करना और नियमों का पालन बेहतर बनाने के लिए विशेषज्ञ परामर्श देना शामिल है।

नियंत्रण से सुविधा प्रदाता की ओर इस बदलाव का उद्देश्यन परस्परर विश्वोस कायम करना और सवोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के साथ तालमेल बिठाना है, इस तरह यह संहिता सहयोगात्मक नियमन और नियोक्ता्ओं और नियामक अधिकारियों के बीच अविश्वास को कम करने पर ज़ोर देती है। साझेदारी को बढ़ावा देकर, यह संहिता नियोक्ताि के लिए अनुपालन को आसान बनाती है। श्रम कानूनों का बेहतर पालन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उत्तरदायी विनियमन की ओर वैश्विक प्रवृत्ति से भी मेल खाती है, जहाँ अनुपालन की नींव बातचीत और भरोसे पर आधारित है।

गैर–अपराधिकरण और स्तरित दंड (या ग्रेडेड पेनल्टी) : इस संहिता के सबसे स्वागतयोग्य सुधारों में से एक है अपराधों को गैर–आपराधिक बनाना। पहले, वेतन से जुड़े उल्लंघन अक्सर लंबी आपराधिक कार्यवाही की ओर ले जाते थे, जो नियोक्ता्ओं के लिए चिंता और देरी का कारण बनते थे। नई रूपरेखा में पहले अनुपालन करने का तरीका अपनाया जाता है, जिससे नियोक्तोओं को अत्यधिक दंडित किए जाने के बजाय गलतियों को सुधारने में मदद मिलती है।

वेतन संहिता में स्तरित दंड या ग्रेडेड पेनल्टी सिस्टम शुरू किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि दंड को उल्लंघन की गंभीरता के मुताबिक निर्धारित किया जाए । यह अपराधों की गंभीरता के आधार पर दंड को श्रेणियों में बांटकर, यह संहिता प्रवर्तन में निष्पक्षता, आनुपातिकता और न्याय को बढ़ावा देने की ओर लक्षित है। छोटी–मोटी गलतियों पर अब कड़ा दंड नहीं मिलेगा, जबकि गंभीर उल्लंघनों पर अब भी उचित दंड दिया जाएगा। अपराधों को संयोजित या कंपाउंड करनाः अपराधों को संयोजित करने का प्रावधान नियोक्तार को लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से बहुत ज़रूरी राहत देता है। पुराने ढाँचे में मामूली, प्रक्रियात्मक गलतियों के लिए भी आपराधिक दंड लगाया जाता था, जिससे लंबी कानूनी प्रक्रिया और नियोक्ताकओं में डर उत्प न्नत होता था। अपराधों को संयोजित करने के तरीके के तहत, कुछ अपराधों को निर्धारित प्राधिकरण को सीधे दंड देकर निपटाया जा सकता है, जो तय अधिकतम जुर्माने के 50त्न के बराबर होता है (धारा 56)। यह सुधार कानूनी देरी को काफी कम करेगा, समाधान प्रक्रिया को आसान बनाएगा, और बिज़नेस को मुकदमेबाजी के खर्चों और अनिश्चितताओं से बचाएगा। नियोक्तार अब बिना किसी रुकावट के अपना काम जारी रखते हुए विवादों को कुशलता से सुलझा सकते हैं।

डिजिटल अनुपालन – कारोबार करने में आसानीः ऐसी दुनिया में जहाँ डिजिटल परिवर्तन तेजी से बढ़ रहा है, नियामक प्रणालियाँ अधिकारीय अड़चनों को कम करने के लिए उसके अनुकूल हो रही हैं। वेतन संहिता इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड–कीपिंग शुरू करके और एकल पंजीकरण और एक रिटर्न फाइलिंग के ज़रिए अनुपालन को आसान बनाकर भारत को इस वैश्विक प्रवृत्ति के साथ जोड़ती है। पहले, व्यिवसाय को विभिन्न वेतन–संबंधी कानूनों के तहत विविध पंजीकरण, फाइलिंग और बहुत सारी कागजी कार्रवाई का सामना करना पड़ता था।

नई प्रणाली इन ज़रूरतों को एक सुचारु डिजिटल प्रक्रिया में बदल देती है। इस आधुनिकीकरण से प्रशासनिक बोझ कम होगा, समय और संसाधन बचेंगे। डिजिटल समाधान को बढ़ावा देकर यह सुधार 'कारोबार करने को सुगम बनाना' के व्यालपक एजेंडे में योगदान देगा और एक प्रतिस्पर्धी वैश्विक अर्थव्यवस्था के तौर पर भारत की स्थिति को मज़बूत करेगा।संतुलित श्रम इकोसिस्टिम बनानाः वेतन संहिता, 2019 सिर्फ श्रमिकों के लिए मात्र सुधार से कहीं बढ़कर है। यह नियोक्ताओं के लिए भी एक बड़ा कदम है, जिन्हें वेतन से जुड़ी अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करने में स्पकष्ट ता, दक्षता और सहायता मिलती है। निरीक्षकों के सुविधा प्रदाता के तौर पर काम करने, अपराधों को गैर–आपराधिक बनाने, स्तरित दंड या ग्रेडेड पेनल्टी, अपराधों को संयोजित करने के प्रावधान और डिजिटल अनुपालन के साथ, यह संहिता निष्पक्षता और जवाबदेही बनाए रखते हुए कारोबार के लिए अच्छा माहौल बनाती है। जैसे–जैसे भारत खुद को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के तौर पर स्थापित कर रहा है, श्रमिकों के अधिकारों और नियोक्ता ओं के काम में आसानी के बीच संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। दोनों पक्षों की चिंताओं को दूर करके, यह संहिता ज़्यादा सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील श्रम बाजार के लिए आधार तैयार करती है, जहाँ अनुपालन को बढ़ावा दिया जाता है, विवादों में कमी आती है, और आर्थिक विकास सामाजिक न्याय एक साथ सुनिश्चित होता है।

यहाँ इस बात का उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वर्तमान में उत्पाद और उसकी पैकेजिंग के डिज़ाइन में अक्सर बदलाव करना पड़ता है, जो ग्राहक की मांग पर निर्भर करता है। यदि निर्धारित अवधि में आपूर्ति किए जाने वाले उत्पाहद की मांग ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में श्रमिक बल को काम के सामान्यप घंटों से ज़्यादा समय तक काम करना पड़ सकता है, जिसके लिए उन्हें ओवर टाइम भुगतान करके सही मुआवज़ा दिया जाएगा। यदि काम के घंटों में कोई कोई सीमा निर्धारित है, तो नियोक्ता को नए कामगार रखने पड़ते हैं जो शायद काम के माहौल से परिचित न हों और उन्हें कार्य वातावरण के अनुकूल बनने में समय लगेगा, जिससे उत्पादन क्षमता पर असर पड़ेगा और उत्पादों की अस्वीकृति होगी, इसलिए, उत्पादन की समय सीमा को देखते हुए मौजूदा कार्यबल को आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त समय काम करने की अनुमति दी जा सकती है।वेतन संहिता, 2019 अपनी श्रम नीति को आधुनिक बनाने की दिशा में भारत का निर्णायक कदम है, जो वैश्विक स्तर पर अधिक न्यायसंगत, सरल और दक्ष नियमन की मांग के अनुरूप है। अनुपालन को आसान बनाकर, प्रक्रिया को डिजिटाइज़ करके, तथा नियोक्ता्ओं और नियामकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर, यह संहिता भारतीय श्रम पद्धति को निष्पक्षता और उत?पादकता के अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ जोड़ती है। यह वेतन संहिता महज एक कानूनी सुधार से कहीं बढ़कर है, जो वेतन कानून को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय दोनों के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में नए सिरे से परिभाषित करती है। यह एक ऐसे श्रम इकोसिस्टम की नींव रखती है जो मज़दूर–केंद्रित और कारोबार के अनुकूल दोनों है, जो भारत के विकसित भारतञ्च2047 की ओर बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है।

# दिल्ली में आतंक का राष्ट्रीय–वैश्विक स्तर वाला धमाका!

**हरिशंकर व्यास**

मतदान से पहले पूरा भारत जब धमाके से भला गूंजा तो मतगणना का दिन बिना धमाके के कैसे होगा? यों 14 नवंबर का दिन नेहरू जयंती का दिन है सो, मामूली बात नहीं जो इस दिन बिहार ने बताया है कि पीढ़ी नई हो, युवा हो, प्रौढ़ हो या बुजुर्ग या फिर महिला व पुरूष और जातियों की टोलीबाजी के सभी मतदाताओं को प्रभावित करता है धमाका, पैसा, झुनझुना और जुमले। सबसे बड़ी बात वोटों की फैक्टरी का वह प्रबंधकीय कौशल, जिसमें ए से ले कर जेड तक के सभी फॉर्मूलों के छब्बीसों विकल्पों के उपयोग का रोडमैप बना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की मशीनरी ने महाराष्ट्र के बाद बिहार में जो ताजा कौशल बताया है वह इस नाते ऐतिहासिक है क्योंकि 140 करोड़ लोगों की भीड़ की 60 प्रतिशत नौजवान आबादी का यह परीक्षाफल जैसा है।

यह परीक्षाफल राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, अखिलेश यादव, आगे ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी या दीपेंद्र हुड्डा, सचिन पायलट, अरविंद केजरीवाल, स्टालिन के बेटे की मुकाबले की क्षमताओं का भी संकेत है। सोचें, तेजस्वी यादव ने क्या नहीं किया? तो उनके लिए जुटी बेइंतहां भीड़ ने जोश दिखलाने में क्या कोई कमी दिखाई? मगर नतीजे उलटे निकले। यह सोचना फिजूल है कि तेजस्वी, प्रशांत किशोर, मुकेश सहनी से उनके समवर्ती चिराग पासवान सियासी तौर पर ज्यादा शातिर हैं। बिहार के इन तमाम चेहरों का, स्थानीय चेहरों का विशेष अर्थ नहीं है। जो है वह मोदी–शाह के ए टू जेड विकल्पों तथा प्रबंधकीय बंदोबस्तों, खरीदफरोख्त के तानेबाने, वोटों की असेंबली लाइन के लिए बनी सप्लाई चेन के फॉर्मूलों का है।

उस नाते परीक्षा में सौ में से सौ नंबर लाने का मोदी–शाह का जुगाड़ सचमुच फिर बेमिसाल साबित हुआ है। इसकी बारीकियों का अनुमान लगाना आसान नहीं है। मेरा मानना है कि मोदी–शाह ने बिहार के चुनाव को इस चुनौती में लड़ा कि जेनरेशन जेड का जो हल्ला बना है उसे बिहार के रास्ते पूरे देश से खत्म किया जाए। निश्चित ही बिहार में बेरोजगारी, बेगारी, गरीबी, पिछड़ेपन की हकीकत से नौजवान आबादी के भभकने के सर्वाधिक खतरे थे। वह अब खत्म है। सो, 14 नवंबर 2025 का बिहार जनादेश भारत के यूथ का कोल्ड स्टोर में निर्वासन है।इससे चुनाव को लेकर अविश्वास निश्चित बढ़ेगा। महाराष्ट्र, हरियाणा के बाद बिहार से भी अविश्वास के विषाणु फैलेंगे। इससे आगे क्या बनेगा इसके जितने अनुमान लगाए वे कम होंगे। बिहार के होहल्ले का मुंह के बल धड़ाम होना मनोवैज्ञानिक तौर पर विपक्ष, खासकर राहुल गांधी, कांग्रेस, अखिलेश, ममता बनर्जी आदि की राजनीति की बोलती बंद करने वाला है। खासकर राहुल गांधी के लिए। उन्होंने बिहार में वह सब किया जो उनके प्रगतिशील सलाहकारों ने सुझाया था। जाति जनगणना, पिछड़ों–दलितों के हक आदि का शोर बना कर उन्होंने मोदी–शाह की जमीन खिसकाने के जितने भी फॉर्मूले अपनाए वे सब बिहार में बेमतलब साबित हुए हैं।

हैरानी का यह सवाल मामूली नहीं है कि ऐसा क्या था जिससे बिहार में जनता दल यू– भाजपा को जिताने के लिए ईवीएम मशीन पर थोक में ठप्पे पड़े? क्या नीतीश कुमार इतने लोकप्रिय हो गए जो उनके पुराने रिकॉर्ड इस चुनाव में टूटे? क्या नरेंद्र मोदी का करिश्मा गुजरी छठ से नए अवतार का नया सूर्योदय है? हाल में ऐसा भला क्या हुआ जो डबल इंजन सरकार ने बुलेट ट्रेन वाला जनादेश पाया?मेरे लिए बिहार के ये नतीजे अपेक्षित थे। मैं तब से ऐसा मानने लगा था जब नीतीश–मोदी सरकार ने घर–परिवार की महिलाओं के खातों में दस–दस हजार रुपए जमा कराना शुरू किया। सरकारी खजाने से लोगों के खातों में इतनी तरह की योजनाओं में खटाखट इतना पैसा जमा हुआ कि निर्धन परिवारों में वह छप्पर फाड़ से कम नहीं था। बिहार निर्धन परिवारों से भरापूरा प्रदेश है। जहां हजार, दो हजार रुपए पर झगड़े हो जाएं, हत्या हो जाए वहां चुनाव से ऐन पहले खजाना खुला मिले तो उसकी माया में वोट क्यों नहीं पकेंगे?

# कीर्ति सुरेश की फिल्म रिवॉल्वर रीटा का ट्रेलर रिलीज़

रिवॉल्वर रीटा का आधिकारिक ट्रेलर जारी कर दिया गया है, जिसमें कीर्ति सुरेश को एक ऐसी कहानी के केंद्र में दिखाया गया है जिसमें साहस, हास्य और तेज़–तर्रार एक्शन का मिश्रण है। नवीना सरस्वती सबधाम (2013) के लिए जाने जाने वाले जे.के. चंद्रू निर्देशन में वापसी कर रहे हैं और इस परियोजना को स्वर और पैमाने के लिहाज से कहीं अधिक महत्वाकांक्षी बना रहे हैं। टीज़र में रीटा को एक गिरोह संघर्ष में फँसा हुआ दिखाया गया है, जहाँ अराजक घटनाओं के कारण उसका रूपांतरण होता है जो उसे तेज़ी और बल के साथ अभिनय करने के लिए मजबूर करती हैं। वहीं ट्रेलर जानबूझकर कथानक के विवरण को छिपाता है और इसके बजाय रीटा के एक खतरनाक क्षेत्र में अप्रत्याशित प्रवेश पर ध्यान केंद्रित करता है।

निर्माण सुधन सुंदरम और जगदीश पलानीसामी द्वारा पैशन स्टूडियो और द रूट बैनर के तहत एक संयुक्त प्रयास है, दोनों ने हाल ही में कई सफल तमिल रिलीज़ का समर्थन किया है। कीर्ति सुरेश के साथ, कलाकारों में राधिका सरथकुमार, सुपर सुब्बारायण, सुनील, अजय घोष, रेडिन किंग्सले, जॉन विजय, कल्याण, सुरेश चक्रवर्ती, कथिरावन, सेंद्रायण, ऑगस्टिन, ब्लेड शंकर, रामचंद्रन, अक्षता अजीत, कुहासिनी और गायत्री शान शामिल हैं, जो फिल्म को एक जीवंत सहायक कलाकार बनाते हैं।

## एशेज सीरीज के इतिहास में इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज

नईदिल्ली, एशेज सीरीज के लंबे इतिहास में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कई दिग्गज बल्लेबाजों ने यादगार पारियां खेली हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बेमिसाल बल्लेबाजी से इतिहास में सुनहरा अध्याय लिख दिया। इन बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ न सिर्फ रन बनाए, बल्कि मैच का रुख बदलने वाली ऐतिहासिक पारियां खेलकर खुद को महान बनाया। आगामी एशेज सीरीज से पहले इंग्लैंड के लिए इस सीरीज के इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं। इस सूची में पहले स्थान पर इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी लियोनार्ड हटन हैं। उन्होंने साल 1938 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ 364 रन की उम्दा पारी खेली थी। द ओवल के मैदान पर इस खिलाड़ी ने 847 गेंदों का सामना किया था। उनके बल्ले से 35 चौके निकले थे। हटन की पारी के दम पर इंग्लैंड ने पहली पारी में 903/7 रन बनाकर पारी घोषित की थी। इंग्लैंड को पारी और 579 रनों से जीत मिली थी। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज टिप फोस्टर हैं। उन्होंने साल 1903 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 287 रन की शानदार पारी खेली थी। फोस्टर इंग्लैंड की पहली पारी में नंबर–5 पर बल्लेबाजी करने उतरे थे।

# टेस्ट क्रिकेट में इन खिलाड़ियों ने 4,000+ रन बनाने के साथ–साथ लिए हैं 300+ विकेट

नईदिल्ली, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक से बढ़कर एक ऑलराउंडर देखने को मिले हैं, जिन्होंने विश्व भर में अपनी छाप छोड़ी है। वर्तमान में रविंद्र जडेजा भी खेल के सबसे बड़े प्रारूप में खासा सफल हुए हैं। उन्होंने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान अहम मुकाम हासिल किया था। वह 4,000+ रन बनाने के साथ–साथ 300+ विकेट लेने वाले खिलाड़ियों में शुमार हुए। आइए इस विशेष सूची के बारे में जानते हैं।

इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर इयान बॉथम ने 102 टेस्ट खेले थे, जिसमें बल्लेबाजी में 33.54 की औसत के साथ 5,200 रन बनाए थे। उन्होंने 14 शतक और 22 अर्धशतक लगाए थे। दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 28.40 की औसत के साथ 383 विकेट लिए थे। उनका पारी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 34 रन पर 8 विकेट लेना रहा है। अपने टेस्ट करियर में बॉथम ने 27 पारियों में 5 विकेट हॉल लिए थे। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर कपिल देव भी इस सूची में शामिल हैं। उन्होंने 131 टेस्ट मैच खेले थे, जिसमें 29.64 की औसत के साथ कुल 434 विकेट लिए थे। उन्होंने 23 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए थे। दूसरी तरफ बल्लेबाजी में उन्होंने 31.05 की औसत के साथ 5,248 रन बनाए थे। पूर्व भारतीय कप्तान ने 8 शतक और 27 अर्धशतक भी लगाए थे, जिसमें 163 रन उनका सर्वोच्च स्कोर रहा था।

# शोले का 50 साल से दबा सच अब आएगा सामने, अंत देख रह जाएंगे दंग

50 साल बाद भारतीय सिनेमा की कालजयी फिल्म शोले एक बार फिर पर्दे पर लौटने जा रही है और इस बार पहले से भी ज्यादा भव्य रूप में। फिल्म को 4के में रिस्टोर कर 1,500 स्क्रीन पर री–रिलीज किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज है इसका असली क्लाइमैक्स, जिसे दर्शक दशकों से सिर्फ सुना करते थे, अब पहली बार वो असली अंत बड़े पर्दे पर दिखेगा। क्या कुछ जानकारी मिली है, आइए जानते हैं।

शोले फिर से सिनेमाघरों में आने वाली है, लेकिन इस बार एक नए रूप में और नए अनुभव के साथ। फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ने इस क्लासिक फिल्म को 4के क्वालिटी में तैयार किया है, जिसे शोले द फाइनल कट नाम दिया गया है। सबसे खास बात यह है कि इस नए वर्जन में दर्शकों को शोले का असली अंत पहली बार देखने को मिलेगा, जिसे अब तक कोई नहीं देख पाया था।

## अजय देवगन की फिल्म दे दे प्यार दे 2 को मिला वीकएंड का फायदा

अजय देवगन इन दिनों एक्शन की बजाय कॉमेडी, रोमांस से दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं। फिल्म 'दे दे प्यार दे 2झ ने शनिवार को बढ़िया कमाई की। वहीं 'कांथाझ, 'हक और 'गर्लफ्रेंड को भी क्या वीकएंड का फायदा मिला है। सैकनिल्क के अनुसार अजय देवगन की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2झ ने दूसरे दिन 12.25 करोड़ की कमाई की है। फिल्म ने ओपनिंग डे पर 8.75 करोड़ रुपये की कमाई की थी। फिल्म का कुल कलेक्शन भी 21 करोड़ रुपये हो चुका है। रविवार को भी इस फिल्म के कलेक्शन में बढ़ोतरी दिख सकती है, क्योंकि वीकएंड पर इसे दर्शक मिल रहे हैं। फिल्म को अंशुल शर्मा ने निर्देशित किया है। इसमें अजय देवगन, रकुल प्रीत के अलावा माधवन भी हैं। यामी गौतम की फिल्म 'हक के लिए भी शनिवार यानी वीकएंड का दिन अच्छी खबर लेकर आया। इस फिल्म का कलेक्शन शुक्रवार को यानी 8वें दिन 65 लाख रुपये रह गया था।

# न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीजः डेरिल मिचेल दूसरे वनडे से हुए बाहर

नईदिल्ली,न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के प्रमुख बल्लेबाज डेरिल मिचेल चोट के कारण दूसरे वनडे मैच से बाहर हो गए हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच में शतक लगाया था और अपनी इस पारी के दौरान वह चोटिल हो गए थे। वह सीरीज के बचे हुए मैचों में खेल पाएंगे या नहीं, इस पर भी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

एनजेडसी ने अपडेट देते हुए कहा, मिचेल रविवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान जांघ में तकलीफ के कारण नेपियर नहीं जा पाएंगे। उनकी बाईं कमर का ऋइस्टचर्च में स्कैन होगा, जिससे बाकी सीरीज के लिए उनकी उपलब्धता तय हो सकेगी। हेनरी निकोल्स को कवर के तौर पर टीम में वापस बुलाया गया है और वह सोमवार को नेपियर में टीम के साथ जुड़ेंगे। निकोल्स ने आखिरी बार इस साल अप्रैल में वनडे मैच खेला था। इस बल्लेबाज ने फोर्ड ट्रॉफी में 76.50 की औसत से 306 रन बनाकर घरेलू रन बनाने की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। उन्होंने ओटागो और ऑकलैंड के खिलाफ पहले और तीसरे राउंड में लगातार दो शतक (117* और 138*) लगाए थे। उन्होंने अपने वनडे करियर में 34.60 की औसत के साथ 2,180 रन बनाए हैं। ऋइस्टचर्च में खेले गए पहले वनडे मैच में मिचेल ने 118 गेंदों में 119 रन की बेहतरीन पारी खेली थी। उनकी बदौलत कीवी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों के बाद 269/7 का स्कोर बनाया था। जवाब में वेस्टइंडीज की पारी पूरे ओवर खेलने के बाद 262/6 का स्कोर ही बना सकी थी। अब दूसरा वनडे मैच 19 नवंबर को खेला जाएगा।

न्यूजीलैंड के कई प्रमुख खिलाड़ी इस सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं हैं, जिनमें फिन एलन (पैर), लॉकी फर्ग्यूसन (हैमस्ट्रिंग), एडम मिल्ने (टखना), विल ओरूके (पीठ), ग्लेन फिलिप्स (ग्रोइन) और बेन सियर्स (हैमस्ट्रिंग) चोट से जूझ रहे हैं।

## संक्षिप्त समाचार

### जयंती पर समारोह 12 से

**जयन्त प्रतिनिधि।**

कोटद्वार : श्री वैश्य अग्रवाल सभा की ओर से महाराज अग्रसेन वार्षिक जयंती समारोह 12 दिसंबर से आयोजित किया जाएगा। जानकारी देते हुए सभा के महामंत्री नरेंद्र कुमार अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम 14 दिसंबर तक चलेगा। इस मौके पर सभा के अध्यक्ष सुबोध गर्ग, नरेंद्र कुमार, संदीप अग्रवाल, अजीत अग्रवाल, प्रदीप अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, रतन अग्रवाल आदि मौजूद रहे।

### छात्रों ने की पुस्तकालय का समय बढ़ाने की मांग

श्रीनगर गढ़वाल : हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विवि में छात्र हितों से जुड़ी मांगों को लेकर आइसा ने सोमवार से हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। बिड़ला परिसर स्थित केंद्रीय पुस्तकालय में वाईफाई सुविधा सुचारु रूप से संचालित किए जाने, विश्वविद्यालय के दोनों पुस्तकालयों के रीडिंग रूम की समय-सीमा बढ़ाकर सुबह 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक किये जाने सहित अन्य मांगों को लेकर छात्र संघ उपाध्यक्ष शिवांक नौटियाल के नेतृत्व में चल रहे हस्ताक्षर अभियान में छात्रों ने बढ़चढ़ कर प्रतिभाग किया। इस दौरान शिवांक नौटियाल ने बिड़ला एवं चौरास परिसर के पुस्तकालयों में हीटर की व्यवस्था किए जाने, पुस्तकालयों में पर्याप्त संख्या में एक्सटेंशन प्लग व बोर्ड उपलब्ध कराए जाने, बिड़ला एवं चौरास परिसर के शौचालयों की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने और विश्वविद्यालय के दोनों पुस्तकालयों के रीडिंग रूम की समय-सीमा बढ़ाकर सुबह 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक किए जाने की मांग की। कहा कि पुस्तकालय सम्बंधित मांगों को लेकर आइसा लम्बे समय से मांग उठा रहा है, परंतु अभी तक इस संबंध में कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। कहा कि मांगों को लेकर आइसा एक सप्ताह तक हस्ताक्षर अभियान चलायेगा। कहा कि यदि मांगों पर जल्द कार्यवाही नहीं होती है तो छात्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस मौके पर पूर्व छात्रा प्रतिनिधि प्रियंका, अंकित उछोली, अतुल सती आदि मौजूद रहे। (एजेंसी)

### धूमधाम से मनाई रेडियो हेंवलवाणी की 24वीं वर्षगांठ

नई टिहरी : चम्बा से संचालित सामुदायिक रेडियो हेंवलवाणी की 24वीं वर्षगांठ धूम धाम से मनाई गई। जिसमें लोक गायकों एवं विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रो आरसी रमोला को सम्मानित किया गया। साथ ही उत्तराखंड ज्ञान प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरूस्कृत किया गया। रविवार को चम्बा में सामुदायिक रेडियो हेंवलवाणी की 24वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष इशिता सजवाण, विधायक प्रतिनिधि सुमन उपाध्याय एवं नगरपालिका अध्यक्ष शोभनी धनोला ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हेवलवाणी रेडियो ने इंटरनेट के इस युग में भी अपने को स्थापित रख कर अपनी लोक संस्कृति एवं बोली भाषा को आगे बढ़ाने और संरक्षण का कार्य कर रहा है। हेंवलवाणी के निदेशक राजेंद्र नेगी ने रेडियो के इतिहास की जानकारी दी। कार्यक्रम में लोक गायक मंजू नौटियाल ने देणा होई बद्री केदारा देणा होई राज रजेश्वरी देणा होई माता भवानी, सुरतू मामा। लोकगायक पदम गुसाई ने देणा होई खोली का गणेशा, देणा होई मौलिका नारयण वर दे। लोक गायक विवेक नोटियाल ने लागी उच्च कैलाश दयौ आदि गीतों से दर्शकों को खूब झूमाया। कार्यक्रम में सरस्वती विद्या मंदिर, स्वामी विवेकानंद, मार्डन स्कॉलर एकेडमी, अनमयूट मेट संगीत एकेडमी के छात्रों अपनी रंगा रंग प्रस्तुति दी। विश्व के शीर्ष दो प्रतिशत वैज्ञानिकों की लिस्ट में स्थान बनाने वाले स्वामी रामतीर्थ के प्रोफेसर एवं वैज्ञानिक आरसी रमोला को सम्मानित किया गया। इस मौके पर राजपाल जड़धारी, बीज बचाओ आंदोलन के प्रणेता विजय जड़धारी, विश्व हिन्दू परिषद के जिलाध्यक्ष यशपाल सिंह सजवाण, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष सूरज राणा, पूर्व जेष्ठ प्रमुख साब सिंह सजवाण, सभासद गौरव फोदड़ी, शक्ति जोशी, अरविन्द मखलोगा, महेश पैन्यूली, प्रधान जसपाल नेगी, पूर्व प्रधान दिनेश भण्डारी, प्रधान परवीन भण्डारी, बीडीसी मेंबर कल्पना पंवार, कवि सोमवारी लाल सकलानी, रेडियो के निदेशक राजेन्द्र नेगी, स्टेशन मैनेजर रवि नेगी, भूपेंद्र तड़ियाल, आरती नेगी, कविता, संगीता राणा, अंकित सजवाण आदि मौजूद रहे। (एजेंसी)

# चुनौती बन रहा अतिक्रमण, नींद में सिस्टम

## स्टेशन रोड में पुलिस की तैनाती के बाद भी सड़क पर सजा रहता है सामान,लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण के कारण आमजन का पैदल चलना भी हुआ मुश्किल

कोटद्वार में स्टेशन रोड पर व्यापारियों द्वारा सड़क में रखा गया सामान

**जयन्त प्रतिनिधि।**

कोटद्वार : शहर में अतिक्रमण आमजन के लिए चुनौती बनता जा रहा है। बावजूद नगर निगम व पुलिस अतिक्रमण को लेकर लापरवाह बनी हुई है। हालत यह है कि स्टेशन रोड में पुलिस कर्मियों की तैनाती के बाद भी सड़क के आधे हिस्से तक अतिक्रमणकारियों का सामान सजा हुआ है। जबकि, प्रतिदिन नगर निगम व पुलिस के अधिकारी भी स्टेशन रोड पर गश्त करते रहते हैं। इसके बाद भी सड़क से अतिक्रमण साफ नहीं होना सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में सबसे अधिक परेशानी शादी व त्योहार सीजन में होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग हो, अथवा शहर को आपस में जोड़ने वाली अन्य मुख्य सड़कें अतिक्रमण व सड़क किनारे खड़े वाहनों के कारण अव्यवस्थाएं चरम पर हैं। सबसे बुरी स्थिति देवी रोड व स्टेशन रोड की बनी हुई है। स्टेशन रोड में पुलिस चौकी से करीब दो सौ मीटर आगे कई व्यापारियों ने सामान सड़क तक सजाया हुआ है। ऐसे में स्टेशन आने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

आधी सड़क पर सजी दुकान के कारण यात्रियों का पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। घंटों जाम की स्थिति बनने के बाद भी यह अतिक्रमणकारी अपना सामान तक नहीं हटाते। जबकि, समीप ही पुलिस कर्मियों की भी तैनाती रहती है। जाम के कारण कई बार पुलिस कर्मी निजी कार चालकों को स्टेशन रोड पर नहीं आने देते हैं। यदि कोई चालक व्यापारियों से सामान हटवाने के लिए कहता है तो वह उससे लड़ने तक को तैयार हो जाते हैं। बावजूद पुलिस कर्मी तमाशबीन बने रहते हैं। क्षेत्रवासी मोहन सिंह ने बताया कि कुछ दिन पूर्व स्टेशन रोड में अतिक्रमण के कारण जाम की स्थिति बनी हुई है। व्यवस्था सुधारने के लिए उन्होंने मौके पर तैनात पुलिस कर्मी से शिकायत की। लेकिन, उल्टा पुलिस कर्मी उन्हें ही नियमों का पाठ पढ़ाने लगा।

### फलाहारी बाबा मंदिर में महोत्सव तीन दिसंबर से

**जयन्त प्रतिनिधि।कोटद्वार :** आद्य सनातन शक्तिपीठ श्री गणेश गिरि धर्मार्थ समिति की ओर से गणेश गिरि फलाहारी बाबा की 88वीं पुण्यतिथि पर महोत्सव का आयोजन तीन दिसंबर से किया जाएगा। इस दौरान महोत्सव को सफल बनाने के लिए सदस्यों को अलग-अलग जिम्मेदारी दी गई बैठक में समिति के सदस्यों ने कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। कहा कि महोत्सव के आचार्य देवी प्रसाद भट्ट रहेंगे। तीन दिसंबर को अखंड रमायण का पाठ किया जाएगा। जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग व संत जन भाग लेते। साथ ही प्राचीन वट वृक्ष के नीचे धूना स्थापित किया जाएगा। सांयकाल में संतों का भंडारा होगा। बताया कि चार दिसंबर को गणेश गिरी फलहारी बाबा की समाधि में स्थित बाबा की मूर्ति का स्नान व अभिषेक करवाया जाएगा। इसके बार भंडारा होगा। बैठक में समिति के सचिव सुमित नेगी, वीरेंद्र सिंह रावत, रणजीत सिंह नेगी, राजेंद्र भंडारी, हेमेंद्र नौटियाल, अनूप रावत, विश्वजीत बड़थ्वाल, नरेंद्र, रविंद्र पाल सिंह, सुमित नेगी आदि मौजूद रहे।

### नियमित तहसीलदार की नियुक्ति नहीं होने पर जताया रोष

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : प्रखंड रिखणीखाल को उपतहसील का दर्जा मिले लगभग एक दशक का समय हो गया हो। लेकिन, तहसील में अभी तक नियमित तहसीलदार की नियुक्त नहीं हो पाई है। साथ ही उपजिलाधिकारी के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। नतीजा, ग्रामीणों को मूल निवास, जन्म प्रमाण पत्र सहित तहसील से संबधित कार्यों के लिए लैंसडौन की दौड़ लगानी पड़ रही है। ग्रामीणों ने रिखणीखाल उपतहसील में स्थाई रूप से तहसीलदार की नियुक्त करने और सप्ताह में दो दिन उपजिलाधिकारी के बैठने की व्यवस्था करवाने की मांग की है। रिखणीखाल से लैंसडौन की दूरी करीब 60 किलोमीटर है। क्षेत्रीय जन को लैंसडौन जाने में आर्थिक नुकसान होने के साथ ही समय की भी बर्बादी होती है। बताना जरूरी है कि करीब एक दशक पूर्व तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में रिखणीखाल को उपतहसील का दर्जा मिला था। लेकिन, लंबे अंतराल के बाद भी उपतहसील में व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हो पाया है। आज भी ग्रामीण लैंसडौन तहसील का चक्कर काटने के मजबूर है। कांडा, तैड़िया, गाडियूं व डिग्री कालेज रिखणीखाल के छात्रों ने ग्राम पंचायत कांडा की ग्राम प्रधान विनीता ध्यानी से इस संबध में चर्चा की। सचिन कुमार, अंकित शिल्पा, जितेंद्र, दीपक, राजेंद्र सिंह, प्रेम सिंह का कहना है कि रिखणीखाल में उपतहसील होने के बावजूद भी उन्हें प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लैंसडौन जाना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी तैड़िया, टकोलीखाल, द्वारी, सिलगांव, डबराड, खनेताखाल, कलीगाड, कोलागाड, पट्टी इडियाकोट, बदलपुर के ग्रामीणों को होती है, जहां से ग्रामीणों को लैंसडौन पहुंचने में चार-पांच घंटे लग जाते हैं ग्राम प्रधान विनीता ध्यानी ने अपर जिलाधिकारी अनिल गर्ब्याल से उपतहसील में स्थाई तहसीलदार की नियुक्ति करने व सप्ताह में दो दिन उपजिलाधिकारी के बैठने की व्यवस्था करवाने की मांग की है।

# भालू ने महिला पर किया हमला, हालत गंभीर

भालू के हमले में घायल महिला

**जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार :** पर्वतीय क्षेत्रों में जंगली जानवरों की धमक थमने का नाम नहीं ले रही। सोमवार को बीरोंखाल ब्लाक के जिवई गांव में भालू ने एक महिला पर हमला कर दिया। महिला को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीरोंखाल पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है।

जानकारी के अनुसार, ग्राम जिवई निवासी लक्ष्मी देवी (40 वर्ष) गांव की अन्य महिलाओं के साथ खेतों में घास लेने के लिए गई हुई थी। इसी दौरान झाड़ियों से निकले भालू ने लक्ष्मी देवी पर हमला कर दिया। आसपास मौजूद अन्य महिलाओं ने शोर मचाना शुरू किया, जिसके बाद भालू वापस जंगल की ओर भाग गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीण महिला को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीरोंखाल पहुंचे। चिकित्सकों ने बताया कि भालू के हमले में महिला की आंख व चेहरे पर गंभीर चोट आई हुई हैं। वहीं, गांव में हुई इस घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। ग्रामीणों ने वन विभाग से भालू के आतंक से निजात दिलवाने की मांग की है। वन क्षेत्राधिकारी वीरेंद्र रावत ने बताया प्रभावित परिवार को तात्कालिक सहायता के रूप में पचास हजार रुपये का मुआवजा दिया गया है। साथ ही प्रभावित क्षेत्र में विभागीय टीम गश्त कर रही है।

# जनता के हित में जरूरी है लालढांग-चिल्लरखाल मार्ग

**जयन्त प्रतिनिधि।**

कोटद्वार में मार्ग निर्माण की मांग को लेकर धरना देते लोग

कोटद्वार : लालढांग-चिल्लरखाल मोटर मार्ग निर्माण की मांग को लेकर लोगों ने चिल्लरखाल में धरना दिया। लोगों ने सरकार से जनता के हित को देखते हुए जल्द से जल्द मार्ग निर्माण करवाने की मांग उठाई। कहा कि जनता की अनदेखी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

लोगों ने धरना देते हुए मार्ग निर्माण की मांग उठाई। कहा कि वह पिछले लंबे समय से मार्ग निर्माण की मांग उठा रहे हैं। लेकिन, अब तक समस्या को गंभीरता से नहीं लिया गया। बताया कि उन्होंने मार्ग निर्माण के लिए कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव किया था। बाजूवद कोई सुध नहीं ली गई।

कहा कि कोटद्वार शहर के विकास के लिए मार्ग निर्माण होना अति आवश्यक है। मार्ग निर्माण से ही क्षेत्र का बेहतर विकास होगा। साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध होगा। वहीं, दिल्ली के चाणक्यपुरी में आयोजित संवाद कार्यक्रम में अधिवक्ता रोहित डंडरियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष लालढांग-चिल्लरखाल मोटर मार्ग निर्माण की मांग रखी। कहा कि जनता के हित को देखते हुए जल्द मार्ग का निर्माण करवाया जाना चाहिए। रोहित डंडरियाल ने बताया कि क्षेत्रीय जनता पिछले लंबे समय से मार्ग निर्माण की मांग उठा रही है। कहा कि कोटद्वार शहर के लोगों ने अब सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। जिससे वह न्यायालय के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकें। कहा कि प्रदेश सरकार को मार्ग निर्माण के लिए गंभीरता दिखानी चाहिए।

# कोतवाली के बाहर से स्कूटी चोरी, 15 दिन बाद भी नहीं चढ़ा हत्थे

कोटद्वार कोतवाली के समीप सीसीटीवी फुटेज में कैद स्कूटी पर हाथ साफ करने वाला युवक

**जयन्त प्रतिनिधि।**

कोटद्वार : लगता है शहर में चोरों के मन से पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। तभी तो 15 दिन पूर्व चोर ने कोतवाली के गेट के समीप से ही एक स्कूटी पर हाथ साफ कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में घटना कैद होने के बाद भी पुलिस अब तक चोर को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ऐसे में शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे है। जबकि, शहरवासी भी लगातार कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की मांग उठाते रहते हैं।

दो नवंबर को बदरीनाथ मार्ग पर ऋचा कुकरेती कोतवाली के समीप स्थित जन औषधि केंद्र में दवा खरीदने के लिए गई हुई थी। करीब दस मिनट के बाद जब वह बाहर निकली तो दुकान के बाहर खड़ी उनकी स्कूटी गायब थी। इधर-उधर पूछने पर भी स्कूटी का कुछ पता नहीं चल पाया, जिसके बाद ऋचा ने प्रतिष्ठानों में लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किए। फुटेज में कोतवाली के गेट के समीप से एक युवक रोड पार कर स्कूटी के नजदीक पहुंचता है। काफी देर तक युवक स्कूटी के समीप खड़ा रहता है। इसके बाद वह सड़क पर चक्कर काटता है और पास की दुकानों व सड़क पर खड़े लोगों के जाने के बाद वह स्कूटी पर चाबी लगाकर उसे झंडाचौक की ओर लेकर चला जाता है। क्षेत्र में इससे पूर्व में कई बार स्कूटी चोरी की घटनाएं सामने आई थी। कुछ माह पूर्व ही पुलिस ने पांच से अधिक स्कूटी के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया था। ऐसे में एक बार फिर चोरी की घटना होने से लोगों में भी खौफ बना हुआ है। वरिष्ठ उपनिरीक्षक राजवीर सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान की जा रही है। जल्द ही बदमाश को स्कूटी के साथ गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

### संस्था ने बच्चों के लिए दिए फर्नीचर व संगीत उपकरण

**जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार:** धनधान्य संस्था की तरफ से जनता इंटर कालेज सुराईडांग (सतपाली) में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों के बैठने के लिए विद्यालय को फर्नीचर व संगीत उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य अतुल मिश्रा व संस्था के निदेशक अमित बहुगुणा ने किया। सर्वप्रथम संस्था की तरफ से विद्यालय के छात्रों के लिए 80 कुर्सिया व टेबल भेंट किए गए। इसके अलावा संस्था ने हारमोनियम, ढोलक व चिमटा भी स्कूल प्रबंधन के सुपुर्द किया। संस्था के निदेशक अमित बहुगुणा ने कहा कि उनकी संस्था कमजोर व अपवंचित छात्रों के लिए लगातार काम कर रही है। कहा कि संस्था का मकसद है कि निर्वल वर्ग के छात्र शिक्षा से वंचित न रहें। कहा कि उनकी संस्था खासकर माता-पिता विहीन छात्रों की शिक्षा के लिए पूर्णरूप से सहयोगी करेगी। इस मौके पर मुकेश बहुगुण, अंकित शर्मा, राहुल पैटवाल, सिमरन शाही, राजीव कुमार, एमबी सांरग, ज्योति पंत, सुनील कुमार, शैलेंद्र मोहन, ललित मोहन, राकेश रावत, बिंदी देवी मौजूद रहे।

### पोखड़ा ब्लॉक में गुलदार की दहशत, बच्चे घरों में कैद

जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : पौड़ी जिले के पोखड़ा में गुलदार के भय से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे है। गुलदार के इस इलाकों में एक के बाद हमलों से जहां स्थानीय ग्रामीण भी दहशत में है वहीं बच्चे स्कूलों तक नहीं जा पा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर ब्लॉक के 12 स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। फिलहाल मंगलवार तक स्कूलों को बंद रखने के आदेश हैं। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय ग्रामीणों की भी पूरी दिनचर्या पिछले चार-पांच दिनों से पटरी से उतरी हुई है। महिलाएं जहां अपने मवेशियों के लिए आस-पास के सटे जंगलों में घास लेने नही जा पा रही है, वहीं अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर संगलाकोटी बाजार जाने में भी ग्रामीण डर रहे हैं। बता दें कि गुलदार ने बीती 13 नवंबर को बगड़ीगाड़ में नाप खेतों में घास काट रही महिला को मार डाला था, इसके बाद इसी गांव से करीब चार किलोमीटर की दूर पर घंडियाल में जंगल में घास लेने गई महिला को गंभीर घायल किया था। गुलदार की सक्रियता को देखते हुए इस पोखड़ा ब्लॉक के 12 स्कूलों को सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया है। इन स्कूलों में एक से लेकर 12वीं तक के बच्चे शामिल हैं। स्कूल 18 नवंबर तक बंद किए गए हैं। पोखड़ा के ब्लॉक प्रमुख संजय गुंसाई ने बताया कि जहां महिला को गुलदार ने घायल किया वह उन्हीं का गांव घंडियाल है। इन दिनों ग्रामीणों में गुलदार की डर बहुत अधिक हो गई है। ग्रामीण शाम होते ही अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। चारापत्ती को लेकर भी परेशानियां आ रही हैं। रोजमर्रा की दिनचर्या गुलदार के हमलों के बाद यहां ठहर सी गई है।

### थराली जनपद गठन की मांग फिर तेज

चमोली : चमोली जिले के थराली विकासखंड में आयोजित बैठक में थराली को जिला बनाने की पुरानी और लगातार उठ रही मांग को नया जोर देने का फैसला किया गया। इस बैठक में एक कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष बख्तर सिंह नेगी, महामंत्री डी.डी उनियाल, और उपाध्यक्ष डी.डी कुनियाल चुने गए। सक्रिय सदस्यों में सामाजिक कार्यकर्ता हीरा सिंह रूपकुंडी, भूधर नेगी, नंदन सिंह रावत, जगदीश प्रसाद थपलियाल, मोहन गिरी, सुभाष पिमोली आदि शामिल हैं। कार्यकारिणी ने प्रस्ताव पारित किया है कि थराली, देवाल और नारायणगढ़ के तीनों तहसीलों को मिलाकर थराली जनपद बनाया जाए। इसके साथ ही संगठन यह भी चाहता है कि थराली विधानसभा क्षेत्र को सामान्य बनाया जाए,जो कि अभी तक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इसके लिए अध्यक्ष व महामंत्री को आंकड़े जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है। जनपद की मांग के पक्ष में तर्क दिया गया कि क्षेत्र में भौगोलिक दूरी और कनेक्टिविटी की चुनौतियां गहरी हैं। थराली से चमोली जिला मुख्यालय (गोपेश्वर) की दूरी लगभग 87 किमी. है, जो प्रशासनिक पहुंच को जटिल बनाती है। जनसंख्या के आंकड़े भी इस मांग को मजबूती देते हैं। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार, थराली तहसील की कुल आबादी लगभग 89,114 थी। ग्रामीण और दुर्गम इलाकों में रहने वाले लाखों लोग वर्तमान व्यवस्था में जरूरी सुविधाओं और सरकारी पहुंच से वंचित महसूस करते हैं।

### गोपेश्वर में पीने के पानी का संकट बढ़ा

चमोली : चमोली जिले के मुख्यालय गोपेश्वर में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। शहर के बड़े हिस्से में करीब 20 हजार की आबादी पिछले कई दिनों से पानी के लिए तरस रही है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि लोग प्राकृतिक स्रोतों और दूरस्थ नदियों की ओर बर्तनों के साथ पानी भरने को मजबूर हैं। गोपेश्वर में अधिकांश आपूर्ति अमृत गंगा पेयजल योजना से होती है। जल निगम ने 11 नवंबर को इस लाइन के सुधारीकरण का कार्य शुरू कर दिया, लेकिन बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के। जल निगम और जल संस्थान के बीच समन्वय न होने के कारण स्थिति और खराब हो गई। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता ने सोशल मीडिया के जरिए केवल कार्य प्रगति की जानकारी दी, जबकि जल निगम के अधिकारी न तो फोन पर उपलब्ध हुए और न ही स्थल पर दिखाई दिए। शहर में पानी की भारी कमी के कारण लोग जगह-जगह भटक रहे हैं।

# छः दशक बाद साकिनखेत रामलीला मंचन की हुई वापसी

**जगमोहन डांगी :**

पौड़ी : जनपद पौड़ी गढ़वाल के मनियारस्यूं और असवालस्यूं पट्टियों के संगम कहे जाने वाले साकिनखेत बाजार में छः दशक के बाद रामलीला का मंचन किया जा रहा है। रामलीला मंचन 21 नवंबर तक किया जायेगा। रविवार को छठें दिन राम भरत मिलाप, सुपर्णखा का नासिका छेदन, रावण मारीच संवाद तक ही रामलीला का मंचन किया गया। रामलीला मंचन में 80 प्रतिशत महिलाएं अपनी भागीदारी निभा रही है।

नयारघाटी म्यूजिकल सांस्कृतिक ग्रुप के निदेशक एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य मवाड़ मनीष कुमार ने बताया कि वह विगत दो वर्षों से साकिनखेत बाजार में रामलीला मंचन के आयोजन का प्रयास कर रहे थे। जो इस वर्ष सार्थक हुआ, क्योंकि छः दशक बाद रामलीला मंचन की शुरुआत करने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्षेत्र के समस्त गांवों के ग्रामवासियों एवं क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से इस वर्ष रामलीला मंचन का मन बना लिया तो उम्मीद से ज्यादा सफल हो रहे है। इसलिए रामलीला समिति बैनर का नाम सामूहिक रामलीला समिति साकिनखेत रखा है। राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न आदि मुख्य किरदार क्षेत्र की बालिकाएं बखूबी निभा रही है। वहीं सुपर्णखा का किरदार भी महिला निभा रही है। बालिकाओं के शानदार अभिनय को देखने भारी संख्या में दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बहुत सालों बाद क्षेत्रवासियों को नए आधुनिक युग में विभिन्न संसाधनों से लैस रामलीला मंचन देखने को मिल रही है। इस मौके पर मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य डोभ श्रीकोट अनुज कुमार, भाजपा के जिला महामंत्री शशि चंद्र रतूड़ी, पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण नेगी, ग्रामीण मंडल उपाध्यक्ष परमानंद सेमवाल, जिला कार्यालय प्रभारी राजेंद्र सिंह रावत, ग्राम प्रधान बेडगांव प्रमोद रावत, रामलीला समिति अध्यक्ष एवं प्रधान बेदल गांव नंदन सिंह रावत, जसपाल सिंह नेगी, ग्राम प्रधान धोड़ा नवीन कुमार, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य सुभाष कुमार सहित ग्रामीण मौजूद थे।

# शहीद त्रिलोक सिंह नेगी स्मृति द्वार का किया लोकार्पण

**जयन्त प्रतिनिधि।**

पौड़ी : कल्जीखाल ब्लॉक के थैर गांव निवासी लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी भारत-चीन की लड़ाई में दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। उनकी स्मृति में बौंसाल में भव्य स्मृति द्वार का निर्माण गया। सोमवार को वीर चक्र विजेता शहीद त्रिलोक सिंह नेगी की 63वीं पुण्यतिथि पर बौंसाल स्मृति द्वार का लोकार्पण सेना अधिकारियों सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने किया।

इस मौके पर भारतीय सेना के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने शहीद त्रिलोक सिंह नेगी को श्रद्धांजलि दी। शहीद त्रिलोक सिंह नेगी ने भारत-चीन की लड़ाई में अद्वितीय शौर्य और पराक्रम दिखाया था। विकासखंड कल्जीखाल और एकेश्वर विकासखंड को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर बौंसाल के पास माँ भारती के वीर सपूत, उत्तरांखण्ड के गौरव, वीर चक्र विजेता शहीद त्रिलोक सिंह नेगी की स्मृति में भव्य स्मृति द्वार बनाया गया है। सोमवार को शहीद त्रिलोक सिंह नेगी की 63वीं पुण्यतिथि पर स्मृति द्वार का विधिवत लोकार्पण किया गया। इस मौके पर मेजर पलमेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी 3 दिसम्बर 1958 को सेना में भर्ती हुए तथा 7 जनवरी 1960 को चतुर्थ बटालियन गढ़वाल राईफल्स का हिस्सा बने। 17 नवंबर 1962 को दुश्मन की एक मशीन गन पोस्ट से भीषण गोलीबारी दुश्मन की तरफ जाने में रूकावट बन रही थी, बटालियन के लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी गांव थैर, पट्टी असवालस्यूं ने राईफलमैन जसवंत सिंह रावत और राईफलमैन गोपाल सिंह गुसांई के साथ मिलकर मशीन गन पोस्ट को नष्ट करने का इरादा बना लिया। परिस्थितियां विषम थी लेकिन खून में उबाल था, असाधारण होसला था भगवान बद्री विशाल की गर्जना के साथ जान की परवाह किए बगैर युद्ध कोशल का सर्वश्रेष्ठ परिचय देकर उन्होंने दुश्मन की मशीन गन को छीन लिया। इस बीच दुश्मन की कई गोलियों से घायल लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी खून की आखरी बून्द और आखरी सांस तक अपने साथियों को कवर फायर देते रहे और अंततः वीरगती को प्राप्त हो गए। उनकी इस असाधारण वीरता कर्तव्य परायणता और सर्वोच्च बलिदान के लिए लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी को वीर चक्र (मरणोपरांत) से सम्मानित किया गया। 17-18 नवंबर 1962 को हुई लड़ाई में तीन अधिकारी, चार जेसीओ, 148 अन्य रैंक और सात एन.सी. ने राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था तथा 300 से अधिक शत्रु मारे गये। इस अवसर पर मेजर पलमेंद्र सिंह चौहान, सेवानिवृत कैप्टन लेखपाल सिंह रावत, राजेंद्र सिंह रावत, पूर्व सैनिक संगठन के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती आरती नेगी, नगर पंचायत अध्यक्ष सतपुली जितेंद्र सिंह चौहान, ब्लॉक प्रमुख एकेश्वर पंकज बिष्ट, ग्राम प्रधान विकास रावत, प्रधान संगठन के अध्यक्ष पंकज पोखरियाल, पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख कल्जीखाल अनिल नेगी, पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष मंजीत रावत, शहीद त्रिलोक सिंह नेगी के परिवार से कुलदीप नेगी, कमल सिंह नेगी, बलदेव सिंह नेगी, आनंद सिंह नेगी, पूर्व कनिष्ठ प्रमुख बलवंत सिंह नेगी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य त्रिभुवन उनियाल आदि मौजूद थे।

### जिला चिकित्सालय में आज होगा सीटी स्कैन मशीन का शुभारंभ

रुद्रप्रयाग : जिला चिकित्सालय में आज मंगलवार को लम्बे इंतजार के बाद सीटी स्कैन मशीन का शुभारंभ किया जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सीटी स्कैन सुविधा होने से अब जनपद के लोगों को अन्यत्र भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा. प्रवीण कुमार ने बताया कि जिला चिकित्सालय में सीटी स्कैन को स्थापित कर दिया गया है।

ट्रायल के साथ ही मशीन के संचालन की भी सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। आज मंगलवार को सीटी स्कैन सुविधा जनता को समर्पित की जाएगी। वही अब यह सुविधा होने से कई बार वाहन दुर्घटना में घायल हुए लोगों को भी सीटी स्कैन के लिए जनपद से बाहर नहीं जाना पड़ेगा जबकि जरूरतमंद लोगों को सभी प्रकार की सुविधा अस्पताल में ही मिलेगी। सीटी स्कैन की सुविधा शुरु होने से ट्यूमर, कैंसर, सिर की चोट, पेट सहित शरीर की कई अन्य समस्याओं का भी आसानी से पता चल सकेगा। (एजेंसी)


## सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे सैन्य अभिलेखों में मेरी पत्नी का नाम लक्ष्मी देवी तथा तहसील व पोस्ट का नाम THALISAN भूलवश दर्ज हो गया है। जबकि मेरी पत्नी का सही व वास्तविक नाम लक्ष्मी देवी ममगाईं (LAXMI DEVI MAMGAIN) है जो कि मेरी पत्नी के आधार कार्ड और पेन कार्ड में अंकित है तथा मेरी तहसील व पोस्ट का सही नाम THALISAIN है। अतः मेरे सैन्य अभिलेखों में मेरी पत्नी का सही व वास्तविक नाम ममगाईं (LAXMI DEVI MAMGAIN) तथा मेरी तहसील व पोस्ट का सही नाम THALISAIN दर्ज किया जाय।

**गिरीश चन्द्र पुत्र श्री दयाल मणी सैन्य संख्या 3600483H रैंक WO ग्राम जखोला, पट्टी चोपड़ाकोट, तहसील थलीसैंण, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।**

**(1514/21)**

## एक नजर

### चाय बागान में खड़कों का खतरा बढ़ा

देहरादून। आशा रोड़ी रेंज के अंतर्गत चाय बागान क्षेत्र में लगातार लगाए जा रहे खड़कों ने स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ा दी है। क्षेत्र निवासी व पशु क्रूरता निवारण समिति के सदस्य कुनाल गौड़ ने इस संबंध में मुख्य वन्यजीव वॉर्डन, उत्तराखंड को विस्तृत शिकायत भेजकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के अनुसार 24 अक्टूबर से लेकर अब तक कई बार चाय बागान की झाड़ियों में खड़के मिल चुके हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह जाल जंगली जानवरों के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं और ये किसी संगठित शिकारी गिरोह की ओर इशारा करते हैं। जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुँची और खड़कों को हटाकर क्षेत्र का निरीक्षण किया। गौड़ ने बताया कि उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को लगातार हो रही संदिग्ध गतिविधियों के बारे में अवगत कराया। चाय बागान क्षेत्र के पास से बार-बार खड़कों का मिलना वन्यजीवों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि वन विभाग की गश्त बढ़ाने के साथ-साथ खड़के लगाने वालों की पहचान कर कठोर कानूनी कार्रवाई आवश्यक है। वन विभाग ने शिकायत को संज्ञान में लेते हुए खड़कों को हटाकर गश्त तेज करने की बात कही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई न की गई तो यह क्षेत्र वन्यजीवों के लिए गंभीर रूप से असुरक्षित हो सकता है।

### माकपा ने उपनल कर्मचारियों और अधिवक्ताओं को दिया समर्थन

देहरादून। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने सोमवार को उपनल कर्मचारियों और अधिवक्ताओं की मांगों के समर्थन में उपजिलाधिकारी सदर हरि गिरी जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। इस दौरान सभी ने मांगें पूरी करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। इस अवसर पर राज्य सचिव राजेन्द्र पुरोहित, देहरादून सचिव अनन्त आकाश, सीटू जिला महामंत्री लेखराज, पार्टी राज्य कमेटी के सुरेन्द्र सिंह सजवाण, शम्भू प्रसाद ममगाई, हिमांशु चौहान, उपाध्यक्ष भगवन्त पयाल, कोषाध्यक्ष रविन्द्र नौडियाल, अनुराधा आदि मौजूद रहे।

### हरबर्टपुर समेत कई गांवों में सात घंटे गुल रही बिजली

विकासनगर। बिजली लाइनों की मरम्मत के चलते सोमवार को हरबर्टपुर कस्बे समेत करीब 25 गांवों में सात घंटे बिजली गुल रही। बिजली गुल होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों को पानी के लिए भी तरसना पड़ा। शाम पांच बजे आपूर्ति सुचारु होने के बाद ही लोगों ने राहत की सांस ली। ऊर्जा निगम वर्तमान में फीडरों में मरम्मत का काम कर रहा है। इस कारण एक सप्ताह तक अलग अलग क्षेत्रों में बिजली कटौती शुरू कर दी गई है। सोमवार को हरबर्टपुर के टिमली फीडर, जमनीपुर फीडर और टाउन फीडर में मरम्मत का कार्य किया गया। बिजली गुल रहने से करीब 45 हजार की आबादी प्रभावित रही। मरम्मत कार्य के कारण सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। टाउन फीडर से हरबर्टपुर बाजार, कोर्ट रोड हरिपुर, ढकरानी, पांवटा रोड, गुडरिच, ढालीपुर, देहरादून रोड, विकासनगर रोड की आवासीय कालोनियों में आपूर्ति बाधित रही। वहीं, जमनीपुर फीडर के जमनीपुर, जमनीपुर तप्पड़, एटनबाग, लक्खनवाला, भगत सिंह कालोनी, फतेहपुर ग्रांट, बैरागीवाला, नया गांव और जस्सोवाला समेत टिमली फीडर से जुड़े टिमली, धर्मावाला, आदूवाला, शाहपुर, कल्याणपुर, प्रतीतपुर, जुडली और फतेहपुर में भी बिजली गुल रही। सुबह 10 बजे से पांच बजे तक बिजली न होने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिजली गुल होने से कई क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति भी ठप रही। हरबर्टपुर मुख्य बाजार में शाम पांच बजे बिजली आपूर्ति बहाल हुई।

### चकराता-लाखामंडल से डामटा तक रोडवेज बस संचालन की मांग

विकासनगर। सात खत किसान संगठन खत अठगांव ने जिलाधिकारी देहरादून को ज्ञापन भेजकर क्षेत्र में रोडवेज की बसें चलाने की मांग की है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को बताया कि खत अठगांव, बोन्दूर, तपलाड़, बिशलाड़, बनगांव और द्वार मोहना के दर्जनों गांवों के लिए परिवहन निगम की कोई सेवा नहीं है। ग्रामीण पिछले चार साल से देहरादून से चकराता-लाखामंडल होते हुए डामटा तक और पुरोड़ी-रावना-डामटा मोटर मार्ग, विकासनगर से क्वांसी तक परिवहन निगम की बसें चलाने को लेकर विभिन्न अधिकरियों और जनप्रतिनिधियों के चक्कर काट रहे हैं,

# हरिद्वार ने जीता राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब

### कंडोलिया में राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन

जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : जिला प्रशासन एवं खेल विभाग के तत्वावधान में कंडोलिया खेल मैदान में आयोजित चार दिवसीय राज्य स्तरीय आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का सोमवार को भव्य समापन हुआ। समापन दिवस पर दो सेमीफाइनल मुकाबलों के साथ ही जिला प्रशासन इलेवन और प्रेस इलेवन के बीच खेले गए मैत्री मैच ने भी दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। फाइनल में हरिद्वार और चंपावत की टीमें आमने-सामने हुई, जिसमें हरिद्वार ने शानदार खेल दिखाते हुए 1-0 से मुकाबला अपने नाम किया। अंतिम क्षणों तक चले रोमांचक मुकाबले में हरिद्वार ने बढ़त बनाए रखकर खिताब पर कब्जा किया। इस मौके पर विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कार वितरित किए गए।

प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों और खेलप्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिला। जिला प्रशासन द्वारा खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की लगातार पहल का परिणाम है कि इस बार बड़ी संख्या में टीमें और दर्शक प्रतियोगिता का हिस्सा बने। कंडोलिया मैदान में चार दिनों से चल रही इस प्रतियोगिता ने न केवल स्थानीय खिलाड़ियों को उत्कृष्ट मंच प्रदान किया बल्कि जिले में खेल संस्कृति को नई ऊर्जा भी दी। समापन अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं में खेल भावना, अनुशासन और टीमवर्क को प्रोत्साहित करते हैं। उन्होंने जिला प्रशासन और खेल विभाग की सराहना करते हुए कहा कि बेहतर प्रबंधन और तैयारी के कारण प्रतियोगिता सफलता पूर्वक संपन्न हुई। फुटबॉल के राष्ट्रीय खिलाड़ी मनीष मैठाणी ने जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया का विशेष आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की सक्रिय भूमिका और समर्थन से पौड़ी में खेलों के लिए बेहतर माहौल तैयार हो रहा है, जिससे स्थानीय खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं

खिलाड़ियों के आत्मविश्वास और भविष्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। जिला क्रीड़ा अधिकारी जयबीर सिंह रावत ने कहा कि जिलाधिकारी की पहल से पौड़ी में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में सभी जनपदों द्वारा प्रतिभाग किया गया। उन्होंने इस प्रतियोगिता का सफल संपादन हेतु जिलाधिकारी का धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने इस प्रतियोगिता में आवश्यक सहयोग देने वाले विभागों में स्वास्थ्य विभाग, जल संस्थान, शिक्षा विभाग, सूचना विभाग, समाज कल्याण, विद्युत विभाग सहित अन्य का भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि आगे ऐसे प्रतियोगिताओं को ओर भव्य रूप में आयोजित किया जाएगा। सेमीफाइनल मुकाबले में पहला मैच बागेश्वर और चंपावत के बीच खेला गया, जिसमें चंपावत ने 1-0 से विजय प्राप्त की। दूसरा सेमीफाइनल देहरादून और हरिद्वार के बीच खेला, जिसका फैसला ट्राई ब्रेकर से 5-3 से हरिद्वार ने देहरादून को हराया। इसके अलावा जिला प्रशासन इलेवन बनाम प्रेस इलेवन का मैत्री मैच भी खास आकर्षण रहा, जिसमें दोनों टीमों ने खेल भावना का शानदार प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला प्रशासन इलेवन ने प्रेस इलेवन को 2-0 से हराया। दर्शकों ने पूरे आयोजन के दौरान खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और जिला प्रशासन की तैयारियों की सराहना की। अपर समाज कल्याण अधिकारी अनिल सेमवाल ने कहा कि युवाओं को नशे से पूरी तरह दूर रहकर अपने जीवन और करियर पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि खेल न केवल व्यक्तित्व निर्माण का माध्यम है, बल्कि बेहतर भविष्य की दिशा भी तय करता है। ऐसे में युवा नशे से दूरी बनाकर फुटबॉल जैसे खेलों में अपनी प्रतिभा निखार सकते हैं और ऊंचाईयों तक पहुंच सकते हैं। फुटबॉल खेल प्रतियोगिता में इनायत हुसैन, प्रवीण नेगी ने मैच में कमेंट्री की। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख अस्मिता नेगी, जिला शिक्षा अधिकारी राजजीत सिंह नेगी, खेल समन्वयक योगंबर नेगी सहित अन्य उपस्थित थे।

# हरीश रावत बोले, मेरे फार्मूले से करो उपनल कर्मचारियों का नियमितिकरण

देहरादून। मुख्यमंत्री हरीश रावत सोमवार को उपनल कर्मचारियों को समर्थन देने परेड ग्राउंड के पास चल रहे धरने में पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार सहमत हो तो उनकी सरकार के दौरान तैयार किए गए फार्मूले से उपनल कर्मचारियों को नियमित कर सकते हैं। साथ ही कहा कि चार-पांच दिन में यह तय नहीं किया गया तो वह खुद दिन-रात उपनल कर्मचारियों के साथ धरने पर बैठेंगे। नियमितिकरण और समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर 10 नवंबर से आंदोलन कर रहे उपनल कर्मचारियों ने सोमवार को यहां यज्ञ किया। उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश संयोजक विनोद गोदियाल ने कहा कि यह यज्ञ सरकार की बुद्धि-शुद्धि के लिए किया गया। यज्ञ के बाद हड़ताली कर्मचारियों के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल पहुंचे। हरीश रावत ने कहा कि जब वह मुख्यमंत्री थे उन्होंने उपनल कर्मचारियों के नियमितिकरण की पूरी तैयार कर दी थी। इसके लिए नीति भी तय कर दी थी, लेकिन विघ्न डालने वालों ने सरकार ही कब्जा ली। अब सत्ता में हैं तो खुद भी नियमितिकरण के लिए कुछ नहीं कर रहे, जबकि कोर्ट बार-बार कहा चुकी है कि इन कर्मचारियों को नियमित करें। इस मौके पर उपनल कर्मचारी महासंघ ने अपनी मृतक साथी नीलम डोभाल के निधन पर दुख जताया। साथ ही कहा कि इतनी दुखद घटना के बाद भी कोई मंत्री-अधिकारी संवेदनाएं प्रकट करने तक नहीं आया।

# साहित्यकार शैलेश मटियानी को मिला "उत्तराखण्ड गौरव सम्मान-2025"

देहरादून। प्रदेश के प्रख्यात हिंदी साहित्यकार स्वर्गीय शैलेश मटियानी को उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार-2025 से सम्मानित किया गया। सोमवार शाम कैंट रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में आयोजित सादगीपूर्ण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मटियानी के पुत्र राकेश मटियानी को पुरस्कार सौंपा। यह सम्मान स्व. मटियानी की साहित्यिक उपलब्धियों, हिन्दी कहानी जगत में उनके अमूल्य योगदान और उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को सशक्त पहचान दिलाने के लिए दिया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मटियानी केवल एक साहित्यकार ही नहीं, बल्कि संवेदनाओं के कुशल शिल्पी थे। आधुनिक हिन्दी कहानी आंदोलन में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने आम जनमानस की पीड़ा, संघर्ष, और जीवन-सत्य को जिस प्रभावशाली शैली में प्रस्तुत किया, वह उन्हें भारतीय साहित्य के श्रेष्ठ रचनाकारों की पंक्ति में स्थापित करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य के उन महान प्रतिभाओं के योगदान को हमेशा सम्मान देती है, जिन्होंने अपनी लेखनी, कर्म और रचनात्मकता से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया है। स्व. मटियानी के "बोरीवली से बोरीबन्दर", "मुठभेड़", "अधागिनी", "चील" सहित अनेक कथा-कृतियाँ आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं और हिन्दी साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। मरणोपरांत यह सम्मान स्वर्गीय मटियानी के परिवार को सौंपना राज्य सरकार के लिए गर्व का विषय है।

### मुख्यमंत्री की छवी चमकाने पर है सरकार का फोकस: गोदियाल

देहरादून। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार उपनल कर्मचारियों की मांगों पर तत्काल कार्यवाही करे। सोमवार को कांग्रेस भवन में मीडिया कर्मियों से बातचीत में गोदियाल ने कहा कि सरकार को केवल छवि चमकाने की चिंता है। बाकी आम आदमी के दुखदर्द से उसे कोई सरोकार नहीं। गोदियाल ने कहा कि यदि वर्तमान सरकार में उपनल कर्मचारियों की सुनवाई नहीं हुई तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर सबसे पहले उपनल कर्मियों की मांगों को पूरा करने की दिशा में काम किया जाएगा। गोदियाल ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक सरकार को केवल अपनी तारीफ सुनने की बजाय, जनता और विपक्ष की आलोचना के लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि आलोचना से ही सरकार को अपनी गलतियों को सुधारने और बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिलता है।

# मुख्य विकास अधिकारी ने किया मिलेट बेकरी यूनिट का औचक निरीक्षण

जयन्त प्रतिनिधि।

रूद्रप्रयाग : मुख्य विकास अधिकारी रुद्रप्रयाग राजेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को ग्राम सन में ग्रामोत्थान एवं उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित उन्नति स्वायत्त सहकारिता नारी अंतर्गत संचालित मिलेट बेकरी सी.बी.ओ. लेवल एंटरप्राइज का औचक निरीक्षण किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से चल रही ऐसी यूनिटें महिलाओं को स्थायी आजीविका, कौशल विकास और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा रही हैं।

निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने बेकरी यूनिट के संचालन, प्रबंधन तथा उत्पादन प्रक्रिया का विस्तृत अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने बेकरी यूनिट में कार्यरत स्वयं सहायता

समूह की महिलाओं से संवाद कर उनकी कार्य प्रणाली, आर्थिक लाभ, चुनौतियों एवं आवश्यकताओं की जानकारी ली। उन्होंने उत्पादों की गुणवत्ता, मार्केट लिंकेज तथा ब्रांडिंग की संभावनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की। सीडीओ ने कहा कि इस प्रकार की इकाइयाँ महिलाओं को घर-गृहस्थी के साथ स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार प्रदान कर रही हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बन रही हैं और ग्राम स्तरीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। मुख्य विकास अधिकारी ने ग्रामोत्थान परियोजना रुद्रप्रयाग को निर्देशित किया कि बेकरी यूनिट में कार्यरत सभी महिलाओं को उचित तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए। एकरूपता एवं पहचान सुनिश्चित करने हेतु सभी महिलाओं के लिए यूनिफॉर्म तैयार की जाए।

बाजार की मांग को देखते हुए यूनिट को गुणवत्तापूर्ण उत्पादन हेतु निरंतर तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जाए। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी द्वारा बेकरी यूनिट को 5 किलोग्राम घी के बिस्कुट तैयार करने का डिमांड ऑर्डर भी दिया गया, जो स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर मुख्य कृषि अधिकारी लोकेन्द्र सिंह बिष्ट आदि मौजूद रहे।

# वरिष्ठ नागरिक समाज की धरोहर : पायल सिंह

### वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा व देखभाल के लिए प्रत्येक नागरिक आगे आएं

जयन्त प्रतिनिधि।

रूद्रप्रयाग : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग सचिव श्रीमती पायल सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को ग्राम पंचायत रतूड़ा में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 पर विधिक शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों, उनकी सुरक्षा, भरण पोषण तथा उनके लिए उपलब्ध कानूनी प्रावधानों की जानकारी प्रदान करना था। कार्यक्रम सचिव ने संदेश दिया कि वरिष्ठ नागरिक किसी भी समाज की धरोहर होते हैं और उनके सम्मान, सुरक्षा व देखभाल के लिए प्रत्येक नागरिक को

आगे आना चाहिए। इस अवसर पर सचिव द्वारा स्थानीय नागरिकों को विभिन्न कानूनी अधिकार, समान शिक्षा-समान अधिकार, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं, एवं नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही जिन प्रमुख बिंदुओं पर जानकारी दी गई उनमें भरण पोषण का अधिकार के तहत माता-पिता एवं वरिष्ठ अपने बच्चों व परिजनों से भरण पोषण की मांग करने, रख-रखाव न्यायाधिकरण के तहत जिला स्तर पर बनाए गए रख-रखाव न्यायाधिकरण में वरिष्ठ नागरिक तेज, सरल एवं निःशुल्क प्रक्रिया द्वारा आवेदन करने, वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध हिंसा, उपेक्षा और दुर्व्यवहार को रोकने के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जानकारी तथा आवास एवं कल्याण प्रावधान के तहत शेल्टर होम, डे-केयर सेंटर एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तृत प्रावधानों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर ग्राम सभा रतूडा के ग्राम प्रधान, रिटेनर अधिवक्ता, असिस्टेंट लीगल एड डिफेन्स काउंसल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी आदि मौजूद थे।

### देहरादून में पूर्व सैनिकों और सैनिक विधवाओं को गृहकर में छूट

देहरादून। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी करनाल ओमप्रकाश पासवान (से नि) ने अवगत कराया है कि देहरादून जिले के सशस्त्र सेनाओं के हवलदार एवं समकक्ष रैंक तक के पूर्व सैनिक और सैनिक विधवायें, जो नगर निगम / नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र में स्वयं के मकान में निवास कर रहे हैं, को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2025-2026 के गृहकर में छूट हेतु आवेदन पत्र 26 नवम्बर 2025 से निशुल्क वितरित और जमा किये जावेगें एवं अन्तिम तिथि 15 मार्च 2026 है। आवेदन पत्र किसी भी कार्यदिवस में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, देहरादून से प्राप्त करें और विधिवत पूर्ण आवेदन पत्र, शपथ पत्र के साथ जमा कर सकते है, जिस हेतु मूल डिस्चार्ज बुक, मूल पहचान पत्र और पिछले साल छूट का आवेदन पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हैं।

# रवांल्टा समुदाय को जौनसार की तर्ज पर आरक्षण के होंगे प्रयास : चौहान

देहरादून। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रमुख मनवीर चौहान ने कहा कि रंवाल्टा समुदाय को जौनसार की तर्ज पर एसटी आरक्षण दिलाने के प्रयास किए जाएंगे।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यमुनोत्री को अलग जिला बनाने का संकल्प भी जल्द पूरा होगा। मनवीर चौहान ने सोमवार को नालापानी रोड स्थित एक वेडिंग प्वाइंट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्पष्ट किया कि यदि युवाओं का समर्थन मिला तो वह 2027 का विधानसभा चुनाव लडेंगे। उन्होंने कहा कि वह पिछले 20 सालों से यमुनोत्री क्षेत्र में विकास कार्यों से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि रंवाल्टा क्षेत्र को आरक्षण की जरूरत है और इस क्षेत्र को अलग जिला बनाने की मांग भी लंबे समय से चल रही है। उन्होंने कहा कि वह इन दोनों ही मांगों को पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि यमुनोत्री क्षेत्र से बड़ी संख्या में देहरादून युवा पढ़ने आते हैं। ऐसे मेंयुवाओं के लिए दून में निशुल्क छात्रावास की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इस अवसर पर वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉ श्रीनंद उनियाल, रिटायर्ड अधिकारी मनमोहन सिंह रावत, प्रोफेसर हुकम सिंह रावत ने भी छात्रों को संबोधित किया। कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सतेंद्र राणा, अतोल रावत, कुलदीप रावत, संदीप राणा, गिरीश भट्ट, निषाद रावत, बाबू बिष्ट, नागेंद्र बिष्ट आदि मौजूद रहे।

# छात्रों को कुष्ठ रोग के लक्षण और उपचार की जानकारी दी

विकासनगर। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मानथात में सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में कुष्ठ रोग जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्रों को रोग के प्रारंभिक लक्षणों, उपचार और रोकथाम की जानकारी दी गई। स्वास्थ्य पर्यवेक्षक बाबूराम तोमर ने बच्चों को बताया कि कुष्ठ रोग के शुरुआती लक्षणों में त्वचा पर सफेद या लाल धब्बे, झुनझुनी, सुन्नपन या दर्द रहित घाव शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि इसका इलाज पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर पहचान कर उपचार लिया जाए तो यह रोग पूरी तरह ठीक हो सकता है। ब्लॉक चकराता के नॉन मेडिकल सुपरवाइजर कृपाराम शर्मा ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को जन जागरूकता का संदेशवाहक बनाना है ताकि वे घर, परिवार और समाज में स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता बढ़ा सकें। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ता और स्वास्थ्य केंद्र समाज तक सही जानकारी पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक रघुवीर सिंह दानू, स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभारी वीर विक्रम सिंह, सुनील सिंह नेगी, किरण ठाकुर, पूजा नौटियाल, ब्लॉक समन्वयक महावीर सिंह राणा, आरकेएस काउंसलर बलबीर सिंह रावत और आशा फैसिलिटेटर निशा रावत आदि मौजूद रहे।

### विधायक से की गौना नदी पर पुल निर्माण की मांग

विकासनगर। रुद्रपुर क्षेत्र में बहने वाली गौना नदी पर पुल निर्माण की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने सोमवार को सहसपुर विधायक सहदेव पुंडीर के कैंप कार्यालय में पहुंच कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने विधायक को बताया कि नदी पर पुल नहीं होने से बरसात के तीन माह तक 20 हजार की आबादी को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कहा कि ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए नौ साल पूर्व गौना नदी पर पुल निर्माण की स्वीकृति प्रदान की थी। इसके बाद भी पुल निर्माण आरंभ नहीं हो सका है। पुल नहीं होने से बरसात के तीन माह अधिकांश ग्रामीण गांवों में कैद होकर रह जाते हैं। बताया कि कुछ साल पहले नदी पार करते हुए सोरना निवासी एक व्यक्ति की बहकर मौत हो चुकी है।

# जनता दरबार में 146 शिकायतें दर्ज

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों पर सोमवार को क्लेक्ट्रेट परिसर में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में जनता दरबार लगाया गया। जनता दरबार में भूमि विवाद, सीमांकन, अतिक्रमण, मार-पीट, भरण पोषण, आपदा से क्षतिपूर्ति सहायता, आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा आदि से जुड़ी 146 समस्या/शिकायतें दर्ज हुई। मुख्य विकास अधिकारी ने मौके पर ही कई मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया साथ ही कुछ प्रकरणों को इससे जुड़े विभागों को अग्रसारित करते हुए विधि सम्मत त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सहस्त्रधारा निवासी 60 वर्षीय बेसहारा बुजुर्ग महिला हरदीप कौर ने आपदा की आपबीती सुनाते हुए बताया

कि आपदा में उनके घर का सारा सामान बह गया है। उसका कोई सहारा नही है और ना ही कोई संतान है। अपने भरण पोषण के लिए उन्होंने कुछ काम करने हेतु आर्थिक सहायता की गुहार लगाई। इस पर राइफल क्लब फंड से बेसहारा बजुर्ग महिला को मौके पर ही 25 हजार का चेक प्रदान किया गया।

# सरकार अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध

जयन्त प्रतिनिधि। चमोली : जिलाधिकारी कार्यालय सभागार, गोपेश्वर में सोमवार को उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष (राज्यमंत्री) मुकेश कुमार की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। अध्यक्ष मुकेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक विभाग में एक नोडल अधिकारी नामित कर योजनाओं की निरंतर मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही एससी/एसटी छात्र-छात्राओं के लिए संचालित छात्रवृत्ति, छात्रावास, कोचिंग, आर्थिक सहायता एवं अन्य योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जाए। बैठक के दौरान अध्यक्ष ने योजनाओं की प्रगति, पारदर्शिता और वास्तविक लाभार्थियों तक उनकी पहुंच की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। इस दिशा में सभी विभागीय अधिकारी जिम्मेदारी से कार्य करें और योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करें। समीक्षा बैठक के पूर्व जिलाधिकारी सभागार में अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधियों ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ एवं कनिष्ठ प्रमुख, साथ ही नगर निकायों के अध्यक्ष व सदस्यों के साथ विस्तृत संवाद आयोजित कर जनपद में अंतिम छोर पर खड़े लोगो से सम्बंधित संचालित योजनाओं का फीड बैक लिया गया। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने-अपने ब्लॉकों में नियमित रूप से भ्रमण कर योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का वास्तविक मूल्यांकन करें और अनुसूचित जाति वर्ग के कितने लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, इसकी नियमित रिपोर्ट उपलब्ध करवाएं। इस दौरान राज्यमंत्री बलवीर घुनियाल, अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य भागीरथी कुंजवाल, अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य विशाल मुखिया, ब्लॉक प्रमुख दशोली विनीता देवी, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी, परियोजना निदेशक आनंद सिंह भकुनी, समाज कल्याण अधिकारी धनंजय लिंगवाल सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

### त्यूनी-चकराता मार्ग पर एक दर्जन से अधिक डेंजर प्वाइंट

विकासनगर। जौनसार बाबर क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अनिल नेगी ने चकराता-त्यूणी और हरिपुर-मीनस सड़क का निरीक्षण किया। इस दौरान जौनसार बाबर क्षेत्र की सबसे पुरानी चकराता-त्यूणी रोड पर एक दर्जन से अधिक डेंजर प्वाइंट चिह्नित किए गए। धारनाधार से लोखडी, कनासर और कोटी के बीच और त्यूना गांव से कचाणूधार, कईलोण खड्ड से दारागाड़ तक कई ऐसे डेंजर प्वाइंट है। वहां पूर्व में बड़े बस हादसे हो चुके हैं। कचाणूधार से लाल पुल तक सड़क की चौड़ाई साढ़े तीन मीटर है। सड़क इतनी संकरी है कि दो कारें पास नही हो सकतीं। यहां ऋश बैरियर भी नहीं लगाए गए हैं। एआरटीओ रावत सिंह कटारिया ने इन प्वाइंट को सबसे खतरनाक बताया। कहा कि रोड सेफ्टी के लिहाज से एनएच रोड पर ऋश बैरियर होने ही चाहिए। यही हाल हरिपुर-मीनस मोटर मार्ग का है। उन्होंने कहा कि हरिपुर से टिक्कर धार तक ऋश बैरियर नही होने से दुर्घटना का खतरा बना रहता है। एआरटीओ ने बताया कि जल्द सड़क का निरीक्षण कर रिपोर्ट सड़क सुरक्षा समिति को सौंपी जाएगी।

जयन्त
संस्थापक
स्व.नरेन्द्र उनियाल
प्रकाशक,मुद्रक और स्वामी
नागेन्द्र उनियाल द्वारा प्रतिभा प्रेस से मुद्रित तथा बद्रीनाथ मार्ग कोटद्वार (गढ़वाल) से प्रकाशित
-सम्पादक
नागेन्द्र उनियाल
आर.एन.आई. 35469/79
फोन/फैक्स 01382-222383
मो. 8445596074, 9412081969
e-mail:
nagendra.uniyal@gmail.com